04 - ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री ने थामा भगवा

05 - जाति जनगणना और पसमांदा मुसलमानों की सामाजिक स्थिति

06 - शहर की चौपाटी को महानगरों की तर्ज पर विकसित करने की...

07 - ट्रिपल आईटीडीएम के गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियों के न्यूड...

सुबह सवेरे

A Daily News Magazine

भोपाल

मंगलवार, 06 मई, 2025

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 22, अंक 236, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

प्रसंगवश

भारत को पाकिस्तान पर इसी तरह दबाव बनाए रखना होगा

ले.जन. एच.एस. पनाग (रि.)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औपचारिक और सार्वजनिक तौर पर साफ इरादा जाहिर कर चुके हैं कि पहलगाम में 26 बेकसूर नागरिकों की बर्बर हत्या करने वालों और उनके आकाओं को इसकी सजा दी जाएगी। 24 अप्रैल को बिहार के मधुबनी में एक जनसभा में उन्होंने कहा- 'अब आतंकियों की बची-खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है।'

प्रधानमंत्री ने सेना को राजनीतिक स्तर पर औपचारिक निर्देश देने के लिए 30 अप्रैल को एक उच्चस्तरीय बैठक की, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने 'सेना की पेशेवराना क्षमता में पूरा भरोसा' जाहिर करते हुए जोर देकर कहा कि 'आतंकवाद को कुचल डालना हमारा राष्ट्रीय संकल्प' है। तीनों सेनाओं को 'हमारे जवाब का तरीका, उसका लक्ष्य, और उसका समय तय करने की पूरी स्वतंत्रता है।' यानी, पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने की तैयारी तो है। केवल यह तय करना बाकी रह गया है कि यह कार्रवाई कब, कैसी, और किस पैमाने पर होगी। और इन सबके बारे में फैसला सेना पर छोड़ दिया गया है। 'कार्रवाई की स्वतंत्रता' के बारे में 'सरकारी सूत्रों' की मासूमियत अपनी जगह है, मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं दिखता कि प्रधानमंत्री ने सैन्य नेतृत्व को अपने राजनीतिक लक्ष्य के अलावा कार्रवाई शुरू करने के समय, उसकी अवधि और पैमाने की राजनीतिक सीमा के बारे में औपचारिक निर्देश दे दिया है। आश्चर्य की बात यह है कि औपचारिक रणनीतिक निर्णय खुले तौर पर किया गया है, जिससे प्रतिद्वंद्वी के मन में अनिश्चितता और दुविधा समाप्त कर दी गई है।

पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध या किसी सैन्य कार्रवाई से नीचे के स्तर की पहल का राजनीतिक लक्ष्य उसे जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के जरिए छद्म युद्ध और दूसरे किसी हिस्से में ऐसी किसी कार्रवाई करने से रोकना है। यह लक्ष्य हासिल करने का फैसला करते समय कई प्रधानमंत्रियों को इस दुविधा का सामना करना पड़ा है। 35 साल पहले जम्मू-कश्मीर में छद्म युद्ध शुरू होने के बाद से, युद्ध से नीचे के स्तर की जो सैन्य कार्रवाइयां की जाती रहीं उन्होंने पाकिस्तान को बाज आने को मजबूर नहीं किया। इन बातों के मद्देनजर कहा जा सकता है कि दिए जाने वाले जवाब का पैमाना हमेशा राजनीतिक फैसले से तय होता है। मौजूदा स्थिति में, सेना प्रधानमंत्री द्वारा तय किए गए राजनीतिक लक्ष्य को किस तरह हासिल करेगी, इसके बारे में अटकलें ही लगाई जा सकती हैं। भारत की कोई औपचारिक घोषित राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति नहीं है, और न इससे जुड़ी कोई राष्ट्रीय प्रतिरक्षा नीति है जिसके आधार पर इस रणनीति को लागू करने की क्षमता बनाई जाए और उसे कायम रखा जाए। पारंपरिक रूप से भारत 'रणनीतिक प्रतिरक्षा' की सैन्य रणनीति का पालन करता रहा है जिसमें युद्ध अपनी ओर से नहीं शुरू किया जाता, और प्रतिद्वंद्वी के आक्रमण का सामना करने के बाद जवाबी कार्रवाई की जाती रही है।

1986 में, जनरल कृष्णस्वामी सुंदरजी ने अगले 15 साल के लिए 'इंडियन आर्मी पर्सपेक्टिव प्लान 2000' नाम के 'विजन पेपर' तैयार किया था, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति, प्रतिरक्षा नीति, और सैन्य रणनीति के आयाम लगभग स्पष्ट किए गए थे। उन्होंने खुद इस पेपर पर दस्तखत किए थे। किसी सेवारत सेनाध्यक्ष द्वारा तैयार किया गया यह इस तरह का पहला और अब तक का अंतिम दस्तावेज़ है। इसमें चीन के खिलाफ 'निवारक प्रतिरोध' और पाकिस्तान के खिलाफ 'आक्रामक प्रतिरोध' तैयार करने, उसे कायम रखने और जरूरत पड़ने पर लागू करने का फैसला किया गया था। भारतीय वायुसेना और नौसेना ने भी इसे स्वीकार किया था।

इसका अर्थ यह था कि चीन का प्रतिरोध प्रतिरक्षात्मक कार्रवाई करते हुए उसकी सैन्य कार्रवाई को सैनिकों और साजोसामान के मामले में बेहद कीमती बनाकर किया जाएगा, जबकि पाकिस्तान को उसकी अधिकतम जमीन पर कब्जा करके और उसकी सैन्य व आर्थिक क्षमता को अधिकतम नष्ट करके सजा दी जाएगी। वास्तव में, सुंदरजी ने इस रणनीति को 1986-87 में दोनों प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ सेना की आक्रामक तैनाती करके लागू किया, जबकि राजनीतिक अनिश्चय के कारण इसे तीखे युद्ध में नहीं बदला गया। यह 'निवारक प्रतिरोध' हमारी भौगोलिक अखंडता को पारंपरिक रूप से खतरा पहुंचाते रहे चीन के खिलाफ काफी सफल रहा है, सिवा तब जबकि उसने हमें हमारे कब्जे से बाहर इलाके में हमें चौंकाया है। सैन्य ताकत के मामले में चीन हमसे बहुत आगे है इसके बावजूद साढ़े तीन साल की तनावपूर्ण तैनाती के बाद अक्तूबर 2024 में लाज बचाने वाला एक समझौता हुआ।

1971 के बाद से पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कोई सीधा पारंपरिक खतरा नहीं पेश किया है। 1989 से चौथी पीढ़ी वाला छद्मयुद्ध छेड़ रखा है, जिसे वह मुख्यतः अपने 'परित्यक्त' नागरिकों के जरिए और जम्मू-कश्मीर के अपने सह-धर्मियों के समर्थन से लड़ता रहा है। पाकिस्तान ने अपनी सेना को इस तरह तैयार किया है कि वह युद्ध से नीचे के स्तर की लड़ाई लड़ सके और इस मामले में भारत की कार्रवाइयों का बराबरी से जवाब दे सके। लेकिन परमाणु हथियार के इस्तेमाल के बगैर सीमित युद्ध में भारत के बेहतर संख्याबल को लेकर वह काफी चिंतित है।

इस मुकाम पर ज्यादा से ज्यादा इलाके पर, खासकर जम्मू-कश्मीर में, कब्जा करने की आक्रामक रणनीति पर आधारित सीमित युद्ध करने और वायुसेना तथा नौसेना के इस्तेमाल से पाकिस्तान की आर्थिक तथा सैन्य शक्ति को नष्ट करने का विकल्प समाप्त हो गया है। यह तभी संभव था जब राजनीतिक फैसला शुरू में ही कर लिया जाता, और तेजी से की गई कार्रवाई के बूते प्रतिद्वंद्वी को अपनी तैयारी करने का मौका दिए बिना चकित किया जाता। ऐसी कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए थी। अब विकल्प यही कि लंबे अंतराल के बाद हमले की पहल की जाए और प्रतिद्वंद्वी को रणनीतिक दृष्टि से चौंका दिया जाए। तात्कालिक लक्ष्य दंड देने की कार्रवाई तक ही सीमित रहेगा जिसे जनभावना को संतुष्ट करने के लिए नियंत्रित युद्ध तक पहुंचाया जा सकता है। पाकिस्तान की 'शाह रग' में खरोंच भी उसे सबसे ज्यादा तकलीफ देगी। मेरे विचार से, पहलगाम हमला बदला लेने की सोची-समझी कार्रवाई थी, और इससे भी ज्यादा यह भारत को हड़बड़ी में सैन्य कार्रवाई के लिए उकसाने के लिए किया गया था। पाकिस्तान यह मान कर चल रहा है भारत की जवाबी कार्रवाई पूर्ण युद्ध से नीचे के स्तर की होगी। बुद्धिमानी तो इसी में है कि पाकिस्तान लंबे समय तक खौफ में रखा जाए।

(दि प्रिंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

तय हो रहा पहलगाम का 'अंजाम'

नई दिल्ली (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए भीषण आतंकी हमले के बाद केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले वायुसेना प्रमुख से मुलाकात की और अब उन्होंने रक्षा सचिव से भी उच्च स्तरीय बैठक कर स्थिति की समीक्षा की है। प्रधानमंत्री पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की करतूत सामने आई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना प्रमुख सहित तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की थी।

यह बैठक 29 अप्रैल 2025 को हुई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह,

● एयर चीफ के बाद रक्षा सचिव से मिले पीएम मोदी ● पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है केंद्र सरकार

● सैन्य तैयारी के साथ आर्थिक नकेल भी कसेगा भारत

मोदी की इन बैठकों को लेकर संकेत मिल रहे हैं कि भारत ठोस जवाब की दिशा में बढ़ रहा है। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए भीषण आतंकी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की जान गई। इस हमले ने देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले के बाद दुनियाभर के देशों ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का समर्थन किया है। इसमें इजरायल, अमेरिका और रूस भी शामिल हैं। पहलगाम आतंकी हमले में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी उपस्थित थे। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सशस्त्र बलों को 'पूरी छूट' दी है कि वह सही तरीके का चयन कर सकें।

● भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ लिए कई ऐक्शन-भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कदम उठाए हैं। इसमें सिंधु जल संधि को रोकना और पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीज़ा सर्विस बंद करना शामिल है। भारत ने पाकिस्तान के दूतावास में काम करने वाले लोगों की संख्या भी कम कर दी है। भारत ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। पाकिस्तान ने कहा है कि पानी रोकने के किसी भी कदम को युद्ध माना जाएगा। उसने यह भी धमकी दी है कि वह सभी समझौते तोड़ देगा, जिसमें शिमला समझौता भी शामिल है। पाकिस्तान का कहना है कि शिमला समझौता नियंत्रण रेखा का उल्लंघन करता है। पिछले कुछ दिनों में, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सुरक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों ने कई मीटिंग की हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के अगले कदम के बारे में बताते हुए कहा कि जो आप चाहते हैं, वह निश्चित रूप से होगा। उन्होंने यह बात प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कही।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंडला ने जिले के रामनगर किला में आयोजित आदि उत्सव में जनजातीय युवाओं के साथ नृत्य कर हितलाभ वितरित किया।

मंडला में 60.62 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन

सीएम बोले- लाड़ली बहनों की राशि बंद नहीं होगी, लेकिन विरोधियों की पार्टी बंद हो जाएगी

मंडला (नप्र)। मंडला के रामनगर में आयोजित आदि उत्सव समापन-सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भाग लेने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पहुंचे थे। यहां पर सीएम ने 585 नव विवाहित जोड़ों समेत लाड़ली बहनों पर फूल बरसाए। इसके बाद सीएम ने 60.62 करोड़ रुपए कीमत के विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन भी किया। जिनमें 40.25 करोड़ की लागत से 10 विकास कार्यों का भूमि पूजन और 20.37 करोड़ की लागत से 24 विकास कार्यों का लोकार्पण शामिल है। कार्यक्रम में पहुंचे कलाकारों के साथ सीएम ने खुद ढोल बजाया। विवाहित जोड़ों का फूलों की बारिश कर सीएम ने स्वागत किया। इसी दौरान सीएम चौगान की मढ़िया पहुंचे, जहां उन्होंने माता के दर्शन-पूजन किया। हृदय शाह के मोती महल में उन्होंने महल का भ्रमण किया और वहां आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। गोंड राजाओं के शौर्य स्मारक पर फूल अर्पित करने के बाद वे सभा स्थल पहुंचे थे।

किसानों को सस्ती बिजली देने की घोषणा की- सभा को संबोधित करते हुए सीएम डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के किसानों को 5 रुपए में बिजली कनेक्शन दिया जाएगा और अगले तीन वर्षों में सोलर पंप के माध्यम से बिजली बिल से मुक्ति दिलाई जाएगी। लाड़ली बहना योजना के तहत उन्होंने कहा, विरोधी कहते हैं कि बहनों की राशि बंद हो जाएगी।

जनजातीय महापुरुषों के सम्मान में टंट्या मामा विश्वविद्यालय की स्थापना की

मुख्यमंत्री ने जनजातीय महापुरुषों जैसे राजा हृदय शाह, राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती, बिरसा मुंडा और टंट्या मामा के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन महापुरुषों ने जल, जमीन, जंगल और जमीर की रक्षा के लिए संघर्ष किया।

भारत सरकार की ओर से खरगोन में टंट्या मामा विश्वविद्यालय की स्थापना को इसका सम्मान बताया। साथ ही, उन्होंने रामनगर और मंडला में गोंड राजाओं के स्मारकों और किलों जैसे मोती महल, रानी महल, राजा शंकर शाह और रानी दुर्गावती से जुड़े स्थलों के विकास की घोषणा की। उन्होंने कलेक्टर सोमेश मिश्रा को रामनगर की मढ़िया के विकास के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए, जिसमें 5 हजार लोगों के लिए सभागार, पेयजल और ठहरने की व्यवस्था शामिल होगी।

कश्मीर में दो हाइड्रो प्रोजेक्ट पर शुरू हो गया है काम

● पानी रोकने के बाद पाकिस्तान पर एक और बड़ी चोट

नई दिल्ली (एजेंसी)। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान को लगातार चोट दे रहा है। घटना के बाद भारत ने दशकों पुरानी सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। वहीं अब भारत ने कश्मीर में दो हाइड्रो प्रोजेक्ट की क्षमता बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। सूत्रों से यह जानकारी मिली है। कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे रहने वाले लोगों ने बताया कि उन्होंने गुरुवार से शनिवार के बीच सलाल और बगलीहार बांधों से पानी छोड़ा जाना देखा। बगलीहार बांध को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से विवाद रहा है। पाकिस्तान ने पहले इस मामले में वर्ल्ड बैंक से मध्यस्थता करने की मांग की थी। रॉयटर्स के अनुसार, भारत की सबसे बड़ी जलविद्युत सरकारी कंपनी एनएच लिमिटेड और जम्मू-कश्मीर के अधिकारियों ने गुरुवार को जलाशय की सफाई की प्रक्रिया शुरू की। इसका मकसद जलाशयों से गाद निकालना है। सूत्रों के अनुसार, सफाई का काम 1 मई से तीन दिनों तक चला। इस काम से पाकिस्तान को तुरंत खतरा नहीं होगा। पाकिस्तान अपनी सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए भारत से आने वाली नदियों पर बहुत अधिक निर्भर है।

तस्लीमा बोलीं, जब तक इस्लाम रहेगा, तब तक आतंकवाद

नई दिल्ली (एजेंसी)। निर्वासित बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने रविवार को पहलगाम आतंकी हमले और ढाका में 2016 के आतंकी हमले के बीच समानताएं बताते हुए कहा कि आतंकवाद तब तक रहेगा जब तक इस्लाम रहेगा। दिल्ली में एक लिट्रेचर फेस्ट के सेशन में उन्होंने कहा कि इस्लाम 1400 साल में भी विकसित नहीं हुआ है। उन्होंने कहा- जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक इस्लाम आतंकवादियों को जन्म देता रहेगा। 2016 में ढाका के हमले में मुसलमानों को इसलिए

कहा-इस्लाम 1400 साल में भी विकसित नहीं हुआ,तर्क और मानवता पर हावी आस्था

मार दिया गया, क्योंकि वे कलमा नहीं पढ़ पाए थे। जब आस्था को तर्क और मानवता पर हावी होने दिया जाता है, तो यही होता है। 22 अप्रैल को दक्षिण कश्मीर के पहलगाम के पास आतंकवादियों ने 26 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी, जिनमें से अधिकतर पर्यटक थे। 1 जुलाई 2016 को आतंकवादियों ने ढाका में होली आर्टिसन बेकरी पर गोलीबारी की थी, जिसमें 29 लोग मारे गए थे। तस्लीमा ईशनिंदा के

आरोपों के बाद नसरीन 1994 से स्वीडन, अमेरिका और भारत में निर्वासित जीवन जी रही हैं। उन्होंने अपने वक्तव्य में यह भी बताया कि यूरोप में चर्च संग्रहालयों में बदल गए हैं, लेकिन मुसलमान हर जगह मस्जिद बनाने में व्यस्त हैं। हजारों मस्जिदें हैं और वे और भी मस्जिदें बनाना चाहते हैं। वे जिहादी पैदा करते हैं। मदरसे नहीं होने चाहिए। बच्चों को सभी किताबें पढ़नी चाहिए, सिर्फएक नहीं।

मुझे भारत से प्यार है, यह घर जैसा लगता है: उन्होंने कहा- मैं संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थायी निवासी हूं। वहां 10 साल तक रही हूं, लेकिन मुझे हमेशा एक बाहरी व्यक्ति जैसा महसूस होता था। कोलकाता आने पर ही मुझे घर जैसा महसूस हुआ। पश्चिम बंगाल से निकाले जाने के बाद भी मुझे दिल्ली में दूसरा घर मिल गया। इस देश ने मुझे अपनेपन का एहसास दिया है, जो मेरा अपना देश नहीं दे सका। बांग्लादेश को लेकर तस्लीमा ने दुख जताया और कहा कि उनके देश में महिलाएं सभी बुनियादी अधिकारों से वंचित हैं।

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

सुप्रभात

मैं लाख कह दूँ कि आकाश हूँ ज़मीं हूँ मैं
मगर उसे तो ख़बर है कि कुछ नहीं हूँ मैं

अजीब लोग हैं मेरी तलाश में मुझ को
वहाँ पे ढूंढ रहे हैं जहाँ नहीं हूँ मैं

मैं आइनों से तो मायूस लौट आया था
मगर किसी ने बताया बहुत हसीं हूँ मैं

वो ज़र्रे ज़र्रे में मौजूद है मगर मैं भी
कहीं कहीं हूँ कहाँ हूँ कहीं नहीं हूँ मैं

वो इक किताब जो मंसूब तेरे नाम से है
उसी किताब के अंदर कहीं कहीं हूँ मैं

सितारो आओ मिरी राह में बिखर जाओ
ये मेरा हुक्म है हालाँकि कुछ नहीं हूँ मैं

यहीं हुसैन भी गुज़रे यहीं यज़ीद भी था
हज़ार रंग में डूबी हुई ज़मीं हूँ मैं

ये बूढ़ी क़ब्रें तुम्हें कुछ नहीं बताएँगी
मुझे तलाश करो दोस्तो यहीं हूँ मैं।

- राहत इंदौरी

मुख्यमंत्री आज हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल के परीक्षा परिणाम करेंगे घोषित

वेबसाइट पर परीक्षा परिणाम उपलब्ध रहेगा

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 6 मई 2025 को शाम 5 बजे मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी एवं विद्यालय पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा (डी.पी.एस.ई.) मुख्य परीक्षा 2025 के परीक्षा परिणाम मुख्यमंत्री निवास (समत्व भवन) में घोषित करेंगे। मण्डल द्वारा विभिन्न पोर्टल के माध्यम से परीक्षा परिणाम ज्ञात करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। निम्न वेबसाईट पर परिणाम परीक्षा उपलब्ध रहेंगे।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 38 °c

न्यूनतम 30°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ मंगलवार, 06 मई 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

राहुल की नागरिकता पर रिपोर्ट पेश नहीं कर पाई सरकार

लखनऊ (एजेंसी)। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताने वाले केस को बंद कर दिया है। कोर्ट ने कहा- राहुल की नागरिकता की रिपोर्ट केंद्र सरकार पेश नहीं कर पाई। कोर्ट ने कहा- केवल रिपोर्ट के इंतजार में याचिका को लंबित नहीं रखा जा सकता। जब भी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्राप्त होती है, तो याचिकाकर्ता को उसकी एक प्रति उपलब्ध कराएं और उसे कोर्ट में भी प्रस्तुत करें। केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि यह मामला दो देशों के बीच की संवेदनशील जानकारी से जुड़ा है। संबंधित देश को कई रिमाइंडर भेजे जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है, इसलिए कुछ और समय दिया जाए।

कोर्ट ने कहा कि फिलहाल इस याचिका की सुनवाई पूरी की जा रही है। याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता है कि वह नागरिकता से संबंधित किसी भी अन्य फोरम या कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है। 21 अप्रैल को हुई सुनवाई में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सूर्यभान पांडेय ने केंद्र की ओर से स्थिति रिपोर्ट पेश की, लेकिन कोर्ट ने उसे अपर्याप्त मानते हुए सख्त टिप्पणी की-यह मामला राष्ट्रीय महत्व का है, देरी नहीं चलेगी। कोर्ट ने केंद्र से पूछा-राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं या नहीं, 10 दिन में स्पष्ट कीजिए। हैरानी की बात यह रही कि राहुल की ओर से कोई वकील अदालत में पेश नहीं हुआ।

जम्मू की जेलों पर आतंकी हमले का सता रहा खतरा

श्रीनगर (एजेंसी)। पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच के बीच जम्मू और कश्मीर में फिर आतंकी साजिश का खतरा मंडरा रहा है। खबरें हैं कि केंद्र शासित प्रदेश की जेलों पर हमले की खुफिया जानकारी है। इधर, पुंछ में भी सुरक्षाबलों को आतंकियों का ठिकाना मिला है, जहां से टिफिन में आईईडी बरामद हुए हैं। फिलहाल, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। खास बात है कि इनमें से कुछ जेलों में बड़े आतंकवादी भी सजा काट रहे हैं। 22 अप्रैल को हुए अटैक के बाद से ही सेना अलर्ट मोड पर है और हमलावरों

की तलाश जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि जम्मू और कश्मीर की जेलों पर संभावित रूप से आतंकी हमला हो सकता है। इसे लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रिपोर्ट में खुफिया इनपुट्स के हवाले से बताया गया है कि आतंकवादी जम्मू में कोट बलवल जेल और श्रीनगर सेंट्रल जेल को निशाना बना सकते हैं। इन जेलों में बड़े आतंकवादियों से लेकर स्लीपर सेल के सदस्य तक बंद हैं। खास बात है कि ये आतंकवादियों को लॉजिस्टिक मदद से लेकर पनाह तक मुहैया कराते थे। खुफिया जानकारी के आधार पर जेलों की सुरक्षा समीक्षा की जा रही है और किसी भी घटना से बचने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

आईएमएफ बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे अय्यर

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बोर्ड में परमेश्वरन अय्यर को अस्थायी डायरेक्टर नॉमिनेट किया है। परमेश्वरन 9 मई को होने वाले आईएमएफ की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। डिप्लोमेटिक लिहाज से शुक्रवार को होने वाली मीटिंग भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि... क्लाइमेट रेजिलिएंस लोन प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को 1.3 बिलियन डॉलर (करीब 11,000 करोड़) के नए लोन पर विचार होगा। पाकिस्तान के लिए जारी 7 अरब डॉलर (करीब 59 हजार करोड़ रुपए) के राहत पैकेज की पहली समीक्षा भी करनी है। पिछले हफ्ते आईएमएफ में भारत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन को बर्खास्त कर दिया गया था।

जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पर बरसीं माया

लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना के मुद्दे पर राजनीति गरमा गई है। बीजेपी के अलावा सपा, बसपा और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के बीच श्रेय लेने को लेकर होड़ मच गई है। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया है। मायावती ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस इसका श्रेय लेकर खुद को ओबीसी हितैषी सिद्ध करने की होड़ है। जबकि इनके बहुजन विरोधी चरित्र के कारण ये समाज अभी भी पिछड़ा, शोषित और वंचित है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट करते कहा कि काफी लंबे समय तक ना-ना करने के बाद अब केंद्र ने राष्ट्रीय जनगणना के साथ जातीय जनगणना भी कराने के निर्णय का भाजपा और कांग्रेस आदि द्वारा इसका श्रेय लिया जा रहा है।

उत्तराखंड में घनघोर बारिश से उफान पर आए नदी-नाले

● ऋषिकेश से मसूरी और केदारनाथ तक जलप्रलय के डर से सहमे लोग

देहरादून (एजेंसी)। वैशाख के महीने में उत्तराखंड में बारिश से आषाढ़ माह जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। प्रदेश में मौसम रौद्र रूप दिखा रहा है। प्रदेश के कई जिलों में बीते तीन दिन से झमाझम बारिश हो रही है। मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा पर्वतीय जिलों में बारिश से जनजीवन अस्तव्यस्त हो रखा है। वहीं बारिश से नदी-नाले उफान पर हैं। मसूरी में भी बारिश से कैंपटी फॉल उफान पर आ गया। वहीं मालदेवता में सोंग नदी में भारी बारिश के कारण मलबा आ गया, जिससे लोग भी दहशत में आ गए। देहरादून में भारी बारिश के कारण मालदेवता में सोंग नदी में अचानक मलबा आ गया और नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ गया। मसूरी और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश से कैंपटी फॉल ने रौद्र रूप दिखाया। झरने के पानी में मलबा आने लगा जो लोगों की दुकानों में घुस गया। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। राज्य के पहाड़ी जिलों में कहीं-कहीं गरज के साथ आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि, तेज बारिश, 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। जिसके लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

वहीं दूसरी ओर मसूरी से 2 किलोमीटर पहले देहरादून मार्ग जेपी बैंड के पास सड़क पर बाहरी मात्रा में मलबा आने से सड़क बंद हो गई। जिससे सड़क के दोनों ओर

वाहनों की लंबी कतार लग गई। बताया जा रहा है कि ठेकेदारों द्वारा बिल्डिंग निर्माण करते समय निकले मलबे को जंगल की ओर सड़क किनारे डाल दिया गया जो रविवार को हुई तेज बारिश के कारण बह कर मुख्य सड़क पर आ गया। जिससे मुख्य सड़क बंद हो गयी। वहीं रविवार की बारिश से मसूरी का कैंपटी फॉल भी रौद्र रूप में दिखा। कैंपटी फॉल का रौद्र रूप देख कर दुकानदार भी दहशत में आ गये और अपनी दुकानें बंद कर वहां से चले गये। वहीं पुलिस ने पर्यटकों को भी एहतियातन झरने में जाने से रोक दिया। घटना के समय कैम्पटी फॉल क्षेत्र में सैकड़ों पर्यटक मौजूद थे, जो झरने के विकराल रूप को देख कर सहम गए। स्थिति को देखते हुए स्थानीय पुलिस ने पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों की ओर भेजा और फॉल में आवाजाही पर रोक लगा दी। दो घंटे में झरने का जलस्तर सामान्य हो गया और व्यवस्था को बहाल कर दिया गया। वहीं मालदेवता में सौंग नदी के उफान पर आने से मजदूरों की झुग्गियां क्षतिग्रस्त हो गईं। उत्तराखंड में मई महीने की बारिश से आसमान से जमकर आफत बरस रही है।

अब अगले सीजेआई करेंगे वक्फ याचिकाओं पर सुनवाई

● भारी विवाद के बीच मौजूदा सीजेआई खींच लिए अपने हाथ

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ याचिकाओं पर सुनवाई 15 मई तक के लिए टाल दी है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने इसे अब अगले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी आर गवई के हवाले कर दिया है क्योंकि अगले सप्ताह वह रिटायर होने जा रहे हैं। उन्होंने अगले सप्ताह अपनी सेवानिवृत्ति का हवाला देते हुए यह व्यवस्था दी। जस्टिस खन्ना 13 मई को रिटायर होंगे, जबकि जस्टिस गवई 14 मई को देश के अगले मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे। सीजेआई खन्ना ने सुनवाई स्थगित करते हुए कहा कि मामले में अंतरिम आदेश पारित करने से पहले लंबी सुनवाई की जरूरत है, जबकि वह अगले सप्ताह ही रिटायर हो रहे हैं। इसलिए, इस मामले को अब अगले चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली पीठ के पास भेजा जाता है। 13 मई को सेवानिवृत्त हो रहे सीजेआई खन्ना ने कहा कि वह कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित नहीं रखना चाहते हैं। पिछली

सुनवाई में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि पीठ द्वारा चिंता जताए जाने के बाद वह वक्फ कानून के दो प्रमुख पहलुओं पर रोक लगा देगा। केंद्र ने 17 अप्रैल को न्यायालय को सूचित किया था कि वह मामले की सुनवाई की अगली तारीख पांच मई तक ''वक्फ बाय यूजर'' सहित अन्य वक्फ संपत्तियों को गैर-अधिसूचित नहीं करेगा, न ही केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्ड में कोई नियुक्तियां करेगा। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीजेआई, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ से कहा था कि संसद द्वारा उचित विचार-विमर्श के बाद पारित कानून पर सरकार का पक्ष सुने बिना रोक नहीं लगाई जानी चाहिए।

पाकिस्तानी रेंजर के बाद अब एक नागरिक भी कब्जे में

● बीएसएफ ने किया गिरफ्तार,रात में फेंसिंग काटकर घुस आया था भारत में

चंडीगढ़/नई दिल्ली (एजेंसी)। 23 अप्रैल से पाकिस्तान के कब्जे में रह रहे बीएसएफ जवान पीके शॉ को पाकिस्तानी रेंजर द्वारा भारत को वापस ना करने के बीच शनिवार-रविवार आधी रात पंजाब में ही भारत-पाकिस्तान बॉर्डर से एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा गया है। यह पाकिस्तानी पंजाब के गुरुदासपुर इलाके में पाकिस्तान बॉर्डर से भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया था। उसी वक्त अलर्ट बीएसएफ जवानों ने इसे दबोच लिया। इसके पास से पाकिस्तान की आईडी मिली है। जिससे इसकी पहचान पाकिस्तानी नागरिक के रूप में हुई है। इस तरह से पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच इसके भारत में घुसने के मंसूबे जानने के लिए इसकी जांइट इंटेरोगेशन की जा रही है। सूत्रों ने बताया कि पकड़ा गया पाकिस्तानी नागरिक करीब 25 साल का है। इसके पास से आईडी के अलावा कुछ करेंसी और अन्य दस्तावेज मिले हैं। जांच की जा रही है कि क्या यह यहां कुछ जासूसी

करने आया था फिर ड्रग्स या हथियार माफिया के लिए काम करता है। खबर लिखे जाने तक इससे पूछताछ की जा रही थी। इस पाकिस्तानी नागरिक को शनिवार-रविवार रात करीब 12 बजे बॉर्डर से पकड़ा गया। बॉर्डर पार करने के लिए इसने वहां लगी फेंसिंग काट डाली थी।

बीएसएफ होगी और मजबूत मिलेंगी 16 नई बटालियन

● पाकिस्तान-बांग्लादेश की सीमाओं के लिए है खास प्लान

नई दिल्ली (एजेंसी)। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगी भारतीय सीमा की चौकसी बीएसएफ के जवान कर रहे हैं। अब बीएसएफ की 16 और बटालियन गठित करने के लिए सरकार की अंतिम मंजूरी मिलने वाली है, जिसमें करीब 17 हजार जवान होंगे। पश्चिमी और पूर्वी कमान के लिए दो अग्रिम मुख्यालय स्थापित किए जाएंगे। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। मंजूरी मिल जाने पर यह बीएसएफ के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, जिसने पिछले वर्ष बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के अपदस्थ हो जाने के बाद पूर्वी मोर्चे पर व 22 अप्रैल को पहलगाम नरसंहार के बाद पाकिस्तान के मोर्चे पर नई चुनौती के मद्देनजर सतर्कता बढ़ा दी है। सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने बताया कि बीएसएफ को 16 नई बटालियन के गठन के लिए जल्द ही अंतिम मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इन बटालियन का गठन अगले कुछ वर्षों में किया जाएगा।

आतंकवाद के खिलाफ भारत को रूस करेगा फुल सपोर्ट

● रूसी राष्ट्रपति का बड़ा ऐलान, इस साल भारत दौरे पर आएंगे ● यूक्रेन वॉर के बाद पहली इंडिया विजिट में रहेंगे राष्ट्रपति पुतिन

नई दिल्ली (एजेंसी)। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को पीएम मोदी को फोन करके पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए 26 लोगों के लिए संवेदना जाहिर की। इसके साथ ही आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में भारत को पूर्ण समर्थन देने की बात कही। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पोस्ट में कहा कि बातचीत के दौरान रूसी राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि हमले में शामिल और उनके पीछे को लोगों को कटघरे में लाया जाना चाहिए। रणधीर जायसवाल एक्स पोस्ट में लिखा- राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया और भारत के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने निर्दोष लोगों की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन देने की बात कही।

भारत-पाक जंग हुई तो सभी पाकिस्तानी दल हो जाएंगे एक

● पाक सेना और राजनीतिक दलों की बैठक में बन गई सहमति ● इमरान की पार्टी ने दिया झटका, मीटिंग से कर लिया किनारा

इस्लामाबाद (एजेंसी)। भारत अगर पाकिस्तान पर हमला करता है तो सभी पाकिस्तानी राजनीतिक पार्टियां एक साथ आ जाएंगे। यह सहमति रविवार देर रात सेना की ब्रीफिंग में के दौरान बनी। दरअसल, सेना ने पहलगाम हमले के बाद बने हालात की जानकारी देने के लिए सभी दलों की बैठक बुलाई थी। सभी पार्टियों ने कहा कि जंग की सूरत में सभी दल एक संयुक्त मोर्चा बना लेंगे। ब्रीफिंग इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और सूचना मंत्री अत्ताउल्लाह तरार ने दी। इसमें इमरान खान की मुख्य विपक्षी पार्टी पीटीआई शामिल नहीं हुई। दरअसल पीटीआई इमरान की जेल से रिहाई की मांग कर रही है, जिसे सरकार ने नकार दिया है। बैठक में राजा परवेज अशरफ, कमर जमान काइरा सहित कई अन्य नेता मौजूद थे।

सिंधु जल समझौता खत्म कर शांत नहीं बैठा है भारत

● अब बंपर बिजली बनाने की योजना पर चल रहा काम

श्रीनगर (एजेंसी)। भारत ने सिंधु नदी प्रणाली पर लगभग 12 गीगावॉट अतिरिक्त जलविद्युत उत्पादन की योजना पर काम तेज कर दिया है। इस योजना के तहत नए जलविद्युत प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन भी शुरू किए गए हैं। दो वरिष्ठ अधिकारियों ने इस संबंध में जानकारी दी। इस नदी प्रणाली पर पहले से जो परियोजनाएं चल रही हैं वे करीब 2.5 जीजी की क्षमता जोड़ेंगी, लेकिन एक अधिकारी के अनुसार, इन परियोजनाओं की प्रगति रुकावटों और सिंधु जल संधि की प्रतिकूल शर्तों के चलते बाधित रही है। अब जबकि भारत ने सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है, तो ऐसे में परियोजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है। 25 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक के बाद, जल शक्ति मंत्रालय और राष्ट्रीय जलविद्युत निगम इन सभी परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत ने 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में

हुए आतंकवादी हमले के एक दिन बाद पाकिस्तान के साथ 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित करने का निर्णय लिया था। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये कदम तब तक प्रभावी रहेंगे, जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद का समर्थन पूर्णतः और स्थायी रूप से समाप्त नहीं कर देता। एक अधिकारी के अनुसार, इन प्रोजेक्ट्स में जम्मू-कश्मीर के रामबन और उधमपुर जिलों में प्रस्तावित सावलकोट प्रोजेक्ट सबसे बड़ा होगा। इन सभी परियोजनाओं को राष्ट्रीय ग्रिड के साथ पूरी तरह जोड़ा जाएगा।

कई राज्यों को मॉकड्रिल करने के निर्देश

● भारत-पाक टेंशन के बीच गृह मंत्रालय का बड़ा कदम

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत-पाक तनाव के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाते हुए कई राज्यों को मॉकड्रिल करने के निर्देश दिए हैं।

सरकार के सूत्रों के मुताबिक, एमएचए से जारी किए गए निर्देश में कहा गया है कि राज्य 7 मई को सुचारू तरीके से नागरिक सुरक्षा को सुनिश्चित कराने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए इस आदेश का समय काफी अहम है क्योंकि ये आदेश ऐसे समय में जारी किया गया है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है और कभी भी जंग छिड़ने जैसा माहौल है।

3 जिलों के अपर कलेक्टर समेत 15 आईएएस जाएंगे मसूरी

उज्जैन, अशोकनगर, कटनी कलेक्टर रहे नीरज, सुभाष व दीपक मिड कैरियर ट्रेनिंग के लिए चयनित

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश के 15 आईएएस अफसरों को मिड कैरियर ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। इनमें उज्जैन, अशोकनगर और कटनी के पूर्व कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, सुभाष कुमार द्विवेदी और दीपक आर्य शामिल हैं। ये ट्रेनिंग 12 मई से 6 जून तक मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में आयोजित की जाएगी।

राज्य शासन ने प्रशिक्षण के लिए इन सभी अधिकारियों को अनुमति दे दी है। इन अफसरों में इंदौर, जबलपुर और सतना के अपर कलेक्टर भी शामिल हैं। यह ट्रेनिंग उन अधिकारियों के लिए अनिवार्य मानी जाती है, जिन्होंने अब तक मिड कैरियर ट्रेनिंग नहीं की है और जिनकी सेवानिवृत्ति में अभी एक साल से अधिक का समय शेष है। इस बार एमपी कैडर के 2012 से 2017 बैच के 15 आईएएस अधिकारियों का चयन हुआ है। राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी ने हाल ही में ऐसे 53 अधिकारियों की सूची जारी की थी, जो अब तक यह ट्रेनिंग नहीं ले सके थे। अब इन्हें चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण में शामिल किया जा रहा है। राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी 2007 से मिड कैरियर ट्रेनिंग का आयोजन कर रही है, ताकि फील्ड में काम कर रहे अधिकारियों की कार्य दक्षता और नेतृत्व क्षमता को और मजबूत किया जा सके।

ये अधिकारी जाएंगे ट्रेनिंग में

- नीरज कुमार सिंह, संचालक परियोजना, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
- दीपक आर्य, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मप्र ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
- सुभाष कुमार द्विवेदी, अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
- एस. कृष्ण चैतन्य, प्रबंध संचालक, मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल
- अंजू पवन भदौरिया, सीईओ जिला पंचायत रायसेन
- शीला दाहिमा, उप सचिव, सहकारिता विभाग
- बिदिशा मुखर्जी, अपर प्रबंध संचालक, एमपी टूरिज्म बोर्ड
- किरोड़ी लाल मीणा, अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
- गौरव बैनल, अपर कलेक्टर, इंदौर
- मिशा सिंह, अपर कलेक्टर, जबलपुर
- स्वप्निल जी. वानखेड़े, अपर कलेक्टर, सतना
- विवेक कुमार, सीईओ जिला पंचायत, ग्वालियर
- रोहित सिसोनिया, अपर आयुक्त, नगर निगम इंदौर
- राहुल नामदेव धोटे, उप सचिव, नर्मदा घाटी विकास एवं जल संसाधन विभाग

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की विशेषज्ञता का लाभ संपूर्ण प्रदेश को समान रूप से मिले : मुख्यमंत्री

सहकारी संघों के साथ निजी डेयरी संचालकों को भी आवश्यक कंसल्टेंसी उपलब्ध कराई जाए

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करना हमारा संकल्प है। इसके लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की डेयरी क्षेत्र में विशेषज्ञता का लाभ संपूर्ण प्रदेश को समान रूप से मिले यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। सहकारी संघों के साथ निजी डेयरी संचालकों को भी आवश्यक कंसल्टेंसी उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए अन्य राज्यों की बेहतर नस्ल की गाय-भैंसों को प्रदेश में लाने और उन्हें किसानों को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि प्रदेश में उत्पादित दूध के वैल्यू एडिशन के बाद ही डेयरी उत्पाद प्रदेश के बाहर जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और म.प्र. राज्य सहकारी दुग्ध संघ के मध्य संपादित अनुबंध के बाद की गई कार्रवाई की समत्व भवन में समीक्षा कर रहे थे। बैठक में पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री लखन पटेल, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रमुख श्री मिनेश शाह, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री एस. रघुपति, महाप्रबंधक श्री संजय गोबानी सहित अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में बड़ी गौशालाएं विकसित की जा रही हैं। इनके विकास और बेहतर प्रबंधन से भी दूध उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि निजी विश्वविद्यालय भी डेयरी टेक्नोलॉजी और एनिमल हसबेंडरी संबंधी कोर्स संचालित करें। विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं के तकनीकी विशेषज्ञों को गौशालाओं से जोड़कर उनके मार्गदर्शन और निर्देशन से गौशालाओं के प्रबंधन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

बैठक में बताया गया कि अनुबंध के परिपालन में प्रदेश के दुग्ध संघों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों का प्रभार राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा नामित मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को सौंपा जा चुका है। निर्देशानुसार प्रदेश की दुग्ध सहकारी समितियों के कव्हरेज क्षेत्र के विस्तार, दुग्ध संकलन, दुग्ध प्रसंस्करण और दुग्ध उत्पादों के लिए अद्यतन तकनीक पर आधारित अधोसंरचना विकसित करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के समन्वय से कार्य जारी है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अगले पांच साल में प्रदेश के कम से कम 50 प्रतिशत गांवों में प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना के लक्ष्य के साथ कार्य कर रहा है। इससे बड़ी संख्या में किसानों को लाभ मिलेगा। किसानों को दूध का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से दुग्ध संघों द्वारा दूध खरीदने की दर में वृद्धि की गई है। दुग्ध संकलन, गुणवत्ता नियंत्रण, भंडारण व्यवस्था आदि की विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा की जा रही है। सम्पूर्ण डेयरी वैल्यू चेन के डिजिटलाईजेशन के अंतर्गत ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन सिस्टम का क्रियान्वयन प्रस्तावित है।

मध्यप्रदेश डेयरी विकास योजना के अंतर्गत डेयरी सहकारी कव्हरेज के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के साथ ही दूध और दूध के उत्पादों के विपणन में सुधार के लिए कोल्ड चैन इन्फ्रास्ट्रक्चर, मिल्क पार्लर स्थापना, ब्राण्ड प्रमोशन, मार्केट स्टडी प्रस्तावित है। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए पशुओं के पोषण और स्वास्थ्य के संबंध में विशेषज्ञतापूर्ण गतिविधियां संचालित की जाएंगी। साथ ही राज्य शासन की किसान कल्याण योजनाओं की डेयरी सहकारी संस्थाओं के समन्वय से क्रियान्वयन के लिए भी पहल होगी।

राज्यमंत्री जायसवाल 6 मई को करेंगे खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का शुभारंभ

भोपाल(नप्र)। कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री दिलीप जायसवाल 6 मई को गौहर महल में राज्य स्तरीय खादी उत्सव 2025 के अंतर्गत खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी ग्रामोद्योग उत्पादों के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं विक्रय के लिये राज्य स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन एक मई से 15 मई 2025 तक किया जाएगा। इस आयोजन में प्रदेश के विभिन्न खादी वस्त्र एवं ग्रामोद्योग सामग्री का उत्पादन एवं विक्रय करने वाली सस्थाओं, इकाईयों एवं प्रदेश के स्व-सहायता समूहों द्वारा भाग लिया जा रहा है। प्रदर्शनी में सभी प्रकार के खादी वस्त्रों एवं ग्रामोद्योग सामग्री पर 20 प्रतिशत छूट का लाभ आमजन को प्रदान किया जाएगा।

सेवानिवृत्त उप संचालक जनसंपर्क नीरज शर्मा को दी श्रद्धांजलि

भोपाल (नप्र)। जनसंपर्क विभाग के सेवानिवृत्त उप संचालक श्री नीरज शर्मा को सोमवार को जनसम्पर्क संचालनालय में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए जनसंपर्क अधिकारियों ने 2 मिनट का मौन रखा

और ईश्वर से प्रार्थना की कि शोकाकुल परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें।

इस अवसर पर अपर संचालक श्री जी.एस. वाधवा श्री संजय जैन, संयुक्त संचालक श्री पंकज मित्तल, श्री मुकेश मोदी, उपसंचालक श्री अरुण राठौर, श्री क्रांति दीप अलूने, उप संचालक श्री टी.के. चटर्जी, श्रीमती बिंदु सुनील, श्रीमती बबीता मिश्रा, श्री संतोष मिश्रा, श्री दुर्गेश रायकवार, मुकेश दुबे, श्री अरुण शर्मा, श्री सुनील वर्मा, सहायक संचालक श्री राजेश पांडेय, सुश्री सोनिया परिहार आदि उपस्थित थे।

नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्तियाँ सुनिश्चित करें : शुक्ल

भोपाल (नप्र)। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़, सुलभ एवं जनोन्मुखी बनाने के लिए कृतसंकल्पित है और इस दिशा में मानव संसाधन की नियमित उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि नियुक्तियों में अनावश्यक विलंब न हो, यह प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति प्रक्रिया को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि परिणाम घोषित होने के पश्चात नियुक्ति में तत्परता बरती जाए एवं समस्त आवश्यक औपचारिकताओं की शीघ्र पूर्ति सुनिश्चित की जाए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और प्रभावी बनाने के लिए चिकित्सकीय मैनपावर की पर्याप्त उपलब्धता अनिवार्य है। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। हर दिन महत्वपूर्ण है, इसलिए नियुक्ति प्रक्रिया की दैनिक समीक्षा एवं फॉलो-अप किया जाए। प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री संदीप यादव, आयुक्त स्वास्थ्य श्री तरुण राठी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की प्रबंध संचालक डॉ. सलोनी सिडाना सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

'जल गंगा संवर्धन अभियान'

राजस्व रिकॉर्ड में जल संरचनाओं को संरक्षण के लिए किया जा रहा है दर्ज

भोपाल (नप्र)। प्रदेश में 30 मार्च से शुरू किया गया 'जल गंगा संवर्धन अभियान' नागरिकों की भागीदारी से सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। यह अभियान समाज के प्रत्येक तबके को महत्वपूर्ण उद्देश्य से जोड़ने में सफल रहा है। प्रत्येक जिले में जल स्रोतों की पहचान की गई है और उनके संरक्षण की दिशा में ठोस कार्य किया जा रहा है। अभियान में प्राचीन बावड़ी के इतिहास की जानकारी नागरिकों को देते हुए इसके सफाई अभियान से नागरिकों को जोड़ा गया है। यह अभियान 30 जून तक चलेगा। अभियान में जल संरचनाओं को राजस्व रिकार्ड में भी जागरूकता के साथ दर्ज किया जा रहा है।

अमृत सरोवर को राजस्व रिकॉर्ड में किया गया दर्ज- उमरिया जिले में अमृत सरोवर को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जा रहा है। जिले में एक मई तक 30 अमृत सरोवरों में से 20 अमृत सरोवरों को राजस्व् रिकार्ड में दर्ज किया जा चुका है। राजस्व अभिलेख में अन्य जल संरचनाएं नहर, तालाब, चेक डेम, स्टॉप डेम इत्यादि को भी अभिलेख मे दर्ज किया गया है। इनकी संख्या 173 है। जिले में नदी, तालाबों, घाटों, कुओं के आस पास श्रमदान करके साफ-सफाई की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जल स्रोतों के आस-पास हुए अतिक्रमण को हटाने की भी कार्रवाई की जा रही है। तहसीलदार मानपुर ने बताया कि चितौहा, नाला डोडका, ताजिया नाला, मझखेता ग्राम पंचायत के अंतर्गत 0.185 हैक्टेयर में हुए अतिक्रमण को हटाने की भी कार्रवाई की गई।

ग्राम पंचायत नरवार व मझौली में किए गए नवीन खेत तालाब के कार्य- शहडोल जिले में जल स्रोतों के संरक्षण के काम को आंदोलन का रूप दिया गया है। जनमानस में यह संदेश दिया गया है कि 'जल को बचाएं, जीवन को बचाएं', 'जब तक जल सुरक्षित है तब तक कल सुरक्षित है।' जिले की समस्त जनपद पंचायत की ग्राम पंचायतों में 'जल गंगा संवर्धन अभियान' में लोग उत्साह एवं उमंग के साथ जल का महत्व समझते हुए श्रमदान कर रहे हैं। नरवार, मझौली ग्राम पंचायत में नवीन खेत तालाब के कार्य किए गए हैं। जनपद पंचायत जयसिंहनगर की ग्राम पंचायत कोठीगढ़ में नदी नालों के साफ सफाई कार्य में श्रमदान किया गया।

जिले के सभी नागरिक कम से कम एक घण्टे श्रमदान अवश्य करें- देवास जिले में जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने हाटपीपल्या विधानसभा क्षेत्र के ग्राम टिगरिया गोगा में जल गंगा संवर्धन अभियान में 4 करोड़ 93 लाख रूपये की

लागत से बनने वाले बैराज का भूमि-पूजन किया। उन्होंने ग्राम टिगरिया गोगा में क्षिप्रा में मिलने वाले नाले की सफाई और गहरीकरण कार्य में श्रमदान किया। उन्होंने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान में जिले के सभी नागरिक कम से कम एक घण्टे श्रमदान अवश्य करें।

मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि केन्द्र और प्रदेश सरकार द्वारा विकसित भारत के लिए कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 सालों में प्रदेश में 100 लाख हैक्टेयर में सिंचाई करने का कार्यक्रम तैयार किया गया है। हाटपीपल्या विधायक श्री मनोज चौधरी ने बताया कि 6 हजार करोड़ रूपये की हाटपीपल्या माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना से विधानसभा के किसानों को लाभ मिलेगा। हाटपीपल्या विधानसभा क्षेत्र में क्षिप्रा नदी पर 26 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से टिगरिया गोगा सहित सात नये बड़े बैराज बनाए जायेंगे। जिसमें गजनोदखेड़ा बैराज, पटाडा बैराज, दखनाखेडी बैराज, रणायर बैराज, सिरोंज बैराज एवं बरोड़ पिपलिया बैराज भी बनाये जायेंगे। इससे नदी में पानी का प्रवाह बना रहेगा।

सामूहिक रूप से डेम का किया गया गहरीकरण

बुरहानपुर जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान जन भागीदारी के साथ उत्साहपूर्वक चलाया जा रहा है। जिले में स्थित प्रत्येक जल स्त्रोतों को चिन्हित कर उनके संरक्षण व साफ-सफाई का कार्य किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में कलेक्टर श्री हर्ष सिंह के निर्देशानुसार नवीन आरटीओ ऑफिस के पास बिरोदा रोड पर स्थित तालाब एवं चेक डेम के पास जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत श्रमदान किया गया। स्टॉप डेम पर श्रृंखला बना कर श्रमदान किया गया। डेम के गहरीकरण का कार्य भी किया जा रहा है। सामूहिक रूप से श्रमदान में बड़े-छोटे पत्थरों को भी तालाब से उठा कर किनारे किया गया। वही एकत्रित किए गए कचरे को ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से उचित जगह निपटान किया गया। तालाब में पानी भराव से पशुओं और जलीय जीवो को भी लाभ मिलेगा।

प्राचीन बावड़ी में की गई साफ-सफाई

विदिशा जिले में ग्यारसपुर बाजरा मठ के समीप स्थित प्राचीन हराऊ बावड़ी में सफाई कर श्रमदान किया गया। इसके साथ ही ग्रामीणों के बीच जल चौपाल भी लगाई गई। ग्रामीणों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई।

श्रमदान के लिए ग्रामीण आ रहे हैं आगे

इंदौर जिले में जल स्रोतों की सफाई का कार्य प्रभावी रूप से किया जा रहा है। जिले में तालाबों, कुँओं, बावड़ियों के गहरीकरण, जीर्णोद्धार के कार्य किये जा रहे हैं। ग्रामीणों को जल संरक्षण के प्रति प्रेरित किया जा रहा है। गाँव-गाँव में जनजागरूकता के कार्यक्रम भी हो रहे हैं। गाँवों में जल यात्रा निकाली जा रही है। ग्रामीणों से चर्चा के लिए जल संवाद कार्यक्रम भी हो रहे हैं। महू विकासखंड में भी रात्रि में आदर्श ग्राम में बैठक ली गई। ग्रामीणों को जल का महत्व बताया गया। जल को संरक्षित करने के लिए प्रेरित किया गया।

चांवरपाठा में आयोजित हुई जल संगोष्ठी

नरसिंहपुर जिले में विकासखंड चांवरपाठा में जल संरक्षण व संवर्धन विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी में बताया गया कि जिले में जल संरक्षण व संवर्धन की दिशा में अनेक कार्य किये जा रहे हैं। बरसात के पूर्व जल संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। इसमें कंटूर ट्रेंच, खेत-तालाब, खंती निर्माण और पुरानी जल संरचनाओं की साफ-सफाई व जीर्णोद्धार के कार्य किये जा रहे हैं। इसके अलावा नागरिकों को अभियान से जोड़ने व जल संचयन के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। यह अभियान सिर्फ शासकीय अभियान नहीं हैं, यह आने वाली पीढ़ी के लिए महत्वपूर्ण अभियान है। आने वाली पीढ़ी के लिए आज से ही हम सभी को जल की एक- एक बूंद को सहेजने का कार्य करना चाहिये।

बैरसिया में तेज रफ्तार कार पलटी, ड्राइवर की मौत

5 महीने की प्रेग्नेंट है मृतक की पत्नी, शादी से लौटते समय हुआ हादसा

भोपाल (नप्र)। शमशाबाद-बैरसिया रोड के महानीम चौराहा पर रविवार-सोमवार की दरमियानी रात तेज रफ्तार कार पलट गई। हादसे में कार चालक की मौत हो गई। कार में सवार तीन अन्य लोग घायल हैं। मृतक की पत्नी पांच महीने की प्रेग्नेंट हैं। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक अनीस खान (40) पुत्र अमीन खान मूल रूप से मंडीबामोरा जिला विदिशा के रहने वाले थे। बीते बीस सालों से भोपाल के काजीकैंप में रहकर कबाड़ बेचने का काम कर रहे थे। रविवार को रिश्तेदार की शादी में शामिल होने सिरोंज गए थे।

वहां से रात करीब 1 बजे भोपाल के लिए लौट रहे थे। शमशाबाद बैरसिया रोड पर उनकी कार बेकाबू होकर पलट गई। कार को अनीस ही ड्राइव कर रहे थे। हादसे में कार सवार अन्य तीन साजिद, बद्दू और बबलू घायल हुए है।

राहगीरों की मदद से पहुंचाया गया अस्पताल

राहगीरों ने उन्हें एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया था। जहां इलाज के दौरान अनीस की सोमवार सुबह मौत हो गई। अस्पताल की सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। सोमवार को पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है।

भारतीय रेल के लिए डिजिटल घड़ी डिजाइन करें

पाएं 5 लाख का राष्ट्रीय पुरस्कार, 31 मई तक भेज सकेंगे डिजाइन

भोपाल (नप्र)। देश की रेल सेवाओं में समयबद्धता और तकनीकी नवाचार को नया आयाम देने के उद्देश्य से भारतीय रेल ने एक अनूठी राष्ट्रीय डिजाइन प्रतियोगिता की शुरुआत की है। इस प्रतियोगिता के तहत देशभर के नागरिकों को रेलवे स्टेशनों पर लगाई जाने वाली डिजिटल घड़ी की नई डिजाइन तैयार करने का अवसर दिया गया है। रेलवे बोर्ड द्वारा संचालित इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विजेता को 5 लाख रुपए का राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। प्रत्येक श्रेणी में पांच प्रतिभागियों को 50,000 रुपए के सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।

भोपाल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि यह प्रतियोगिता भारतीय रेल के नवाचार प्रयासों और जनसहभागिता का परिचायक है। समय प्रबंधन को नई पहचान देने का यह सुनहरा मौका है। उन्होंने भोपाल मंडल के छात्रों, कलाकारों, डिजाइनर्स और आम नागरिकों से इस प्रतियोगिता में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है।

तीन श्रेणियों में आमंत्रित हैं डिज़ाइन

स्कूली छात्र (12वीं कक्षा तक)
कॉलेज/यूनिवर्सिटी विद्यार्थी
पेशेवर डिजाइनर एवं आम नागरिक

डिजाइन भेजने की डेडलाइन 31 मई

प्रतिभागी 1 मई से 31 मई 2025 तक अपनी डिजाइन केवल ऑनलाइन माध्यम से भेज सकते हैं। डिजाइन हाई-रेजोल्यूशन में और वाटर मार्क रहित होनी चाहिए।

डीएमई नियुक्ति पर प्रदेशभर की मेडिकल फैकल्टी में आक्रोश

काली पट्टी बांध कर रहे इलाज, जूडा ने किया विरोध प्रदर्शन

भोपाल (नप्र)। प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सोमवार को जूनियर डॉक्टर और मेडिकल शिक्षकों ने एक बार फिर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध की वजह डॉ. अरुणा कुमार को डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन (डीएमई) के पद पर नियुक्त किया जाना है। मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन (एमटीए) और जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन (जूडा) ने इस फैसले को दबाव का नतीजा बताया है।

भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, नीमच, मंदसौर, रतलाम और विदिशा समेत सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों ने

सोमवार को दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक सांकेतिक प्रदर्शन किया। वे मरीजों का इलाज काली पट्टी बांधकर करते दिखे। इस दौरान मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग के नाम ज्ञापन भी डीन के माध्यम से सौंपा गया।

भोपाल में जुटेंगे मेडिकल टीचर्स- एमटीए मध्यप्रदेश की वीडियो कांफ्रेंसिंग में तय किया गया कि अगर सरकार ने सोमवार तक डॉ. अरुणा कुमार को डीएमई बनाने का आदेश वापस नहीं लिया, तो उग्र आंदोलन होगा। एमटीए भोपाल के अध्यक्ष डॉ. राकेश मालवीय का कहना है कि प्रदेश के सभी 18 सरकारी और स्वशासी मेडिकल कॉलेजों से एमटीए के पदाधिकारी राजधानी के लिए कूच करेंगे। यहां एक मंच पर एकत्र होकर धरना देंगे।

गांधी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) समेत प्रदेशभर के मेडिकल संस्थानों में इन दिनों एक ही नाम चर्चा में है, डॉ. अरुणा कुमार। वजह है हाल ही में जारी हुआ आदेश, जिसमें उन्हें डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन (डीएमई) पद की जिम्मेदारी दी गई है। गुरुवार शाम जैसे ही यह आदेश सार्वजनिक हुआ, प्रदेश के मेडिकल सेक्टर में विरोध शुरू हो गया। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन (जूडा) से लेकर मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन (एमटीए) तक इस फैसले के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। डॉ. अरुणा कुमार के प्रशासनिक कार्यकाल को लेकर पहले भी विवाद होते रहे हैं। हर बार जब उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी गई, उसी के साथ विरोध भी सामने आया।

जब-जब जिम्मेदारी मिली, विरोध भी हुआ

- साल 2000 में डॉ. कुमार को सुल्तानिया अस्पताल में स्त्री रोग विभाग की प्रमुख बनाया गया। सूत्रों के अनुसार, उनके कार्यकाल में 25 से ज्यादा विभाग से जुड़े स्टाफ ने नौकरी छोड़ी।
- साल 2017 में नर्सिंग स्टाफ ने भी उनके खिलाफ प्रदर्शन किया था।
- साल 2018 में वह पहली बार जीएमसी की डीन बनीं, लेकिन साल 2019 में छात्रों के विरोध के चलते उन्हें पद से हटाया गया। तत्कालीन कलेक्टर ने अपनी जांच रिपोर्ट में उन्हें छात्रों के प्रति असंवेदनशील बताया था।
- साल 2020 में दोबारा डीन बनीं, लेकिन मेडिकल टीचर्स और स्टाफ से टकराव के चलते उन्हें फिर हटाना पड़ा।
- साल 2023 में बाला सरस्वती आत्महत्या मामले के बाद उन्हें विभागाध्यक्ष पद से हटाकर डीएमई में स्थानांतरित किया गया।
- जनवरी 2024 में जब उन्हें स्त्री रोग विभाग में वापस भेजने का आदेश जारी हुआ, तो जूडा ने काम बंद कर हड़ताल कर दी। मामला बढ़ता देख उपमुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा और आदेश निरस्त हुआ।
- मई साल 2025 यानी अब जब उन्हें प्रदेश की मेडिकल शिक्षा प्रणाली की सबसे ऊंची जिम्मेदारी डीएमई पद सौंप दी गई है तो एक बार फिर जूडा से लेकर एमटीए विरोध में आ गया है।

संपादकीय

अल्बनीज व वोंग की जीत!

ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर से भारत के लिए दो अच्छी खबरें हैं। वहां हुए आम चुनाव में जो नेता और पार्टियां जीती हैं, वो भारी बहुमत के साथ न सिर्फ सत्ता में लौटीं हैं बल्कि उनका रवैया भारत मित्र का है। मसलन ऑस्ट्रेलिया के आम चुनाव में प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की लेबर पार्टी ने इकतरफा जीत हासिल की है। अल्बनीज दोबारा देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। चुनाव में लेबर पार्टी ने 150 में से 86 सीटें जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। अल्बनीज की इस जीत के पीछे उनका मूलमंत्र है, किसी को रोका नहीं गया और किसी को पीछे नहीं छोड़ा गया। अल्बनीज 2022 में देश के प्रधानमंत्री बने थे। वह ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए बड़ी राहत की बात थी। क्योंकि उनके पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री स्कॉट मारिसन बहुत अलोकप्रिय रहे थे। देश में राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक संकट की स्थिति बन रही थी। लेकिन अल्बनीज ने हालात को कुशलता से संभाला। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की कोशिशों को बढ़ावा दिया. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय संबंधों को स्थिर करने और प्रमुख नीतिगत बदलावों को लागू करना शुरू कर दिया। 61 साल के अल्बनीज का बचपन अभावों में बीता। युवावस्था तक उन्हें अपने पिता का पता नहीं था। वे राजनीति में आए और 1996 में 33 साल की उम्र में पहली बार सिडनी की एक स्थानीय सीट के लिए चुने गए। अब वे देश के सबसे लंबे समय तक सांसद रहने वालों में से हो गए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की मुफ्त स्वास्थ्य सेवा को बचाकर रखने के लिए सम्मान पाया। साथ ही एलजीबीटी समुदाय के पैरोकार, रग्बी के एक उत्साही प्रशंसक और ऑस्ट्रेलिया के गणतंत्र बनने का समर्थन करने वाले के रूप में उन्होंने काफी लोकप्रियता हासिल की। अल्बनीज 2007 में पहली बार मंत्री बने। उन्हे मध्यमार्गी माना जाता है। अल्बनीज के सामने बड़ी चुनौती ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने की है, जो कोविड के बाद से खराब चल रही है। देश में महंगाई बढ़ी हुई है। लोगों के लिए आवासों की भारी कमी है। उनकी पिछली सरकार ने देश में 15 लाख किफायती घर बनाने का वादा किया था। हालांकि देश को उनसे बड़े आर्थिक सुधारों की अपेक्षा है। ऐसा नहीं है कि अल्बनीज का पिछला कार्यकाल पूरी तरह बेदाग रहा हो। उनके कार्यकाल पर सबसे बड़ा धब्बा अक्टूबर 2023 का द वॉयस जनमत संग्रह है। जिसके तहत आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट द्वीप में रहने वालों को संवैधानिक मान्यता देना था और साथ ही उनके लिए एक संसदीय सलाहकार निकाय स्थापित करनी थी। लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। लेकिन मतदाताओं ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जहां तक भारत की बात है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे बहुत अच्छे सम्बंध रहे हैं। लाखों भारतीय ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। इसके अलावा भारत हिंद महासागर की सामूहिक निगरानी करने वाले उस क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग (क्वाड) का सदस्य है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। उधर सिंगापुर के आम चुनाव में प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की प्रचंड जीत हुई है। उनकी पीपुल्स एक्शन पार्टी (पीएपी) ने संसद की 97 में से 87 सीटें जीतकर सत्ता पर अपनी पकड़ कायम रखी। पीएपी सिंगापुर में 50 साल से सत्ता पर काबिज है। खास बात है कि ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर दोनो देशों में ही भारतीयों की प्रभावी उपस्थिति है और वे राजनीतिक रूप से भी अपनी आवाज दमदार तरीके से उठाते रहे हैं। हमारे इन दोनों देशों के साथ व्यापारिक और शैक्षणिक सम्बन्ध भी हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दोनो प्रधानमंत्रियों की जीत की बधाई देते हुए परस्पर रिश्तों के और मजबूत होने की अपेक्षा की है। वैसे भी वर्तमान हालात में इन देशों में भारतमित्र सरकारों का होना हमारे लिए बेहद खास है।

ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री ने थामा भगवा

मार्च 2023 में अल्बनीज ने भारत का दौरा किया था, जहां उन्होंने और प्रधानमंत्री मोदी ने रणनीतिक साझेदारी के तहत सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई थी। ऑस्ट्रेलिया में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं, और दोनों नेताओं ने नियमित रूप से लोगों के बीच संबंधों को द्विपक्षीय संबंधों की प्रमुख धुरी के रूप में उजागर किया है। ऑस्ट्रेलिया की राजनीति में 21 सालों में पहली बार है जब सिटिंग प्रधानमंत्री को लगातार दोबारा में सत्ता में आने का मौका मिला है। ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति में निरंतरता के लिए एक जनादेश के रूप में देखा जा रहा है, खासकर इंडो-पैसिफिक के लिए इस जीत को भारत बेहतर मान रहा है।

नजरिया

अशोक भाटिया

लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।

ऑस्ट्रेलिया में एक बार फिर एंथनी अल्बनीज का जादू चला है। उनकी लेबर पार्टी ने संघीय चुनाव जीत लिया है। इसके साथ ही अल्बनीज लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। कुछ समय पहले अल्बनीज ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'दुनिया का बॉस' बताया था। अब ऑस्ट्रेलिया की जनता ने उन्हें फिर से बॉस चुन लिया है। इसके साथ ही अल्बनीज 21 सालों में दोबारा चुनाव जीतने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री बन गए हैं।

ऑस्ट्रेलिया में शनिवार को आम चुनाव में महंगाई और आवास की कमी जैसे मुद्दे छाए रहे। मतदान सुबह आठ बजे शुरू हुआ। इससे पहले डाक मतदान 22 अप्रैल को ही शुरू हो गया था। ऑस्ट्रेलिया उन गिने चुने देशों में शामिल है, जहां मतदान करना अनिवार्य है। साल 2022 में हुए पिछले आम चुनाव में 90 फीसदी मतदान हुआ था। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज दूसरा कार्यकाल पाने की कोशिशों में जुटे थे। उनका मुकाबला कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पीटर डटन से था।

ऑस्ट्रेलिया संसद में दो सदन हैं। ऊपरी सदन को सीनेट और निचले सदन को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स (प्रतिनिधि सभा) कहा जाता है। भारत की तरह ही निचले सदन में बहुमत पाने वाली पार्टी या गठबंधन का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है। इसकी 150 सीटों के लिए अभी वोटिंग हुई थी। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल की अच्छी-खासी आबादी है। इस बार चुनाव में भारतीय मूल के 8 लाख मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे है। भारतीय मूल के वोटर्स को लुभाने के लिए सियासी दलों ने अपनी-अपनी रणनीति बनाई थी। प्रधानमंत्री की पार्टी ने भारतीय छात्रों के लिए वीजा की संख्या बढ़ाने का वादा किया है। इतना ही नहीं, वर्क वीजा बढ़ाने का भी मुद्दा चुनाव में छाया हुआ है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री अल्बनीज भारत के साथ संबंधों को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं का वायदा किया था।

विपक्ष के नेता पीटर डटन अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। उन्हें लेबर पार्टी की उम्मीदवार अली फ्रांस ने हरा दिया। चुनाव के नतीजे आने के बाद डटन ने अपनी हार मान ली और अल्बनीज को फोन करके बधाई दी। अगर लेबर पार्टी को बहुमत मिलता है, तो अल्बनीज ही प्रधानमंत्री रहेंगे। वे अपनी पार्टी के नए सदस्यों में से मंत्रियों को चुनेंगे।

अब बात करते हैं एंथनी अल्बनीज की। उन्हें लोग प्यार से 'अल्बो' भी कहते हैं। वे 2004 के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लगातार दो चुनाव जीते हैं। 61 साल के अल्बनीज को कुत्तों से बहुत प्यार है। वे साधारण परिवार से आते हैं और उनका अंदाज काफी सहज रहता है। स्थानीय मीडिया ने भी मान लिया है कि अल्बनीज और उनकी लेबर पार्टी चुनाव जीत गई है। शुरुआती नतीजों से पता चलता है कि लोगों ने लेबर पार्टी को खूब वोट दिया है।

अल्बनीज का बचपन मुश्किलों भरा रहा। उनका जन्म मार्च 1963 में हुआ था। उनकी मां अकेली थीं और उन्हें पेंशन पर गुजारा करना पड़ता था। वे सिडनी में सरकारी घर में रहते थे। दिलचस्प बात यह है कि उन्हें बचपन में बताया गया था कि उनके पिता मर चुके हैं। लेकिन किशोरावस्था में उन्हें पता चला कि उनकी मां शादीशुदा आदमी से गर्भवती हुई थीं जो शायद अभी भी जिंदा थे। तीस साल बाद उन्होंने अपने पिता कार्लो अल्बनीज को ढूंढा और उनसे मिलने इटली गए। लेकिन अल्बनीज मानते हैं कि उनकी मां के साथ बिताए शुरुआती सालों ने उन्हें वह इंसान बनाया जो वे आज हैं। वे अपने परिवार में हाई स्कूल पास करने वाले पहले व्यक्ति थे और उन्होंने सिडनी यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में डिग्री हासिल की। उनका राजनीति से पहला नाता यूनिवर्सिटी में जुड़ा जहां वे छात्र परिषद में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने लेबर पार्टी के मंत्री टॉम उरेन के साथ काम किया और फिर एनएसडब्ल्यू लेबर के सहायक महासचिव बने।

अल्बो को लोग 'छोटी-छोटी बातों पर ज्यादा ध्यान न देने वाला' मानते हैं, जो एक नेता के लिए अच्छी बात है। वे पार्टियों और चुनावी कार्यक्रमों में 'डीजे अल्बो' के नाम से गाने भी बजाते हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीवी पर भी वे अक्सर अपने प्यारे कुत्ते 'टोटो' के साथ दिखाई दिए थे। 1996 में अपने 33वें जन्मदिन पर अल्बनीज पहली बार संसद के लिए चुने गए। तब से वे लगातार सांसद हैं और ऑस्ट्रेलिया के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले सांसदों में से एक हैं। उन्होंने लगभग 30 साल तक सिडनी की सीट का प्रतिनिधित्व किया है।

2007 में जब लेबर पार्टी सत्ता में आई तो अल्बनीज बड़े मंत्री बने और पार्टी के नेताओं को बदलने में उनकी अहम भूमिका रही। उन्होंने केविन रड को हटाकर जूलिया गिलार्ड को प्रधानमंत्री बनवाया और फिर वापस केविन रड को लाए। केविन रड के दूसरे छोटे कार्यकाल में वे उप-प्रधानमंत्री भी रहे। 2013 में उन्होंने विपक्ष के नेता के लिए चुनाव लड़ा।

2019 में जब लेबर पार्टी अप्रत्याशित रूप से चुनाव हार गई तो उन्होंने निराश पार्टी का नेतृत्व किया। लेकिन अल्बनीज ने हार नहीं मानी और अपना काम जारी रखा। आखिरकार 2022 में उन्होंने देश का सबसे बड़ा पद जीत लिया और लिबरल-नेशनल गठबंधन के दस साल के शासन को खत्म कर दिया।

अल्बनीज जल्दी ही शादी भी करने जा रहे हैं। उनकी मंगेतर का नाम जोडी हेडन है। वह प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए शादी करने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री होंगे। उन्होंने पिछले साल ही शादी करने का इरादा जाहिर किया था। बाद में उन्होंने शादी को टालने का ऐलान कर दिया। अल्बनीज ने कुछ समय पहले कहा था कि वे चुनाव के बाद और साल खत्म होने से पहले (2025 में ही) शादी करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका फिर से चुना जाना ऑस्ट्रेलियाई जनता का उनके नेतृत्व पर 'स्थायी विश्वास' को दर्शाता है। अल्बनीज ने उच्च-स्तरीय राष्ट्रीय चुनाव के बाद अपनी जीत का ऐलान किया है, जिसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बधाई दी।

प्रधानमंत्री मोदी ने अल्बानीज को टैग करते हुए अपने एक्स पोस्ट में कहा, 'आपकी शानदार जीत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में पुनर्निर्वाचन के लिए बधाई एंथनी अल्बानीज यह जीत आपके नेतृत्व पर ऑस्ट्रेलियाई जनता के स्थायी विश्वास को दर्शाती है।' प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों इंडो-पैसिफिक लोकतंत्रों के बीच बढ़ती साझेदारी पर भी जोर दिया और अल्बनीज सरकार के साथ क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। उन्होंने कहा, 'मैं भारत-ऑस्ट्रेलिया रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने और इंडो-पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा रणनीतियों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने की उम्मीद करता हूं।'

मार्च 2023 में अल्बनीज ने भारत का दौरा किया था, जहां उन्होंने और प्रधानमंत्री मोदी ने रणनीतिक साझेदारी के तहत सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई थी। ऑस्ट्रेलिया में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं, और दोनों नेताओं ने नियमित रूप से लोगों के बीच संबंधों को द्विपक्षीय संबंधों की प्रमुख धुरी के रूप में उजागर किया है। ऑस्ट्रेलिया की राजनीति में 21 सालों में पहली बार है जब सिटिंग प्रधानमंत्री को लगातार दोबारा में सत्ता में आने का मौका मिला है। ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति में निरंतरता के लिए एक जनादेश के रूप में देखा जा रहा है, खासकर इंडो-पैसिफिक के लिए इस जीत को भारत बेहतर मान रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी व ऑस्ट्रेलिया की नजदीकी के कारण ऑस्ट्रेलिया भारतीय छात्रों का सबसे पसंदीदा स्टडी डेस्टिनेशन बन गया है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया अब भारतीय छात्रों के लिए सबसे पसंदीदा अंतरराष्ट्रीय स्टडी डेस्टिनेशन बन गया है। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा प्रदाता द्वारा मार्च 2025 में कराए गए Emerging Futures Seven – Voice of the International Student सर्वे के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है। ऑस्ट्रेलिया की इस बढ़त का श्रेय उसकी मजबूत वैश्विक रैंकिंग और भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते को दिया गया है, जिसने पोस्ट-स्टडी वर्क राइट्स को और आकर्षक बना दिया है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025 में ऑस्ट्रेलिया की 15 यूनिवर्सिटीज टॉप 200 में शामिल हैं।

सर्वे में शामिल लगभग 6,000 वैश्विक छात्रों में से 1,400 भारतीय छात्र थे। इनमें से 28 प्रतिशत भारतीय छात्रों ने ऑस्ट्रेलिया को अपनी पहली पसंद बताया, जबकि अमेरिका 22 प्रतिशत के साथ दूसरे और यूके 21 प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर रहा। कनाडा की लोकप्रियता में भारी गिरावट आई है, जो पिछले वर्ष के 19 प्रतिशत से घटकर अब मात्र 13 प्रतिशत रह गई है। हालांकि अमेरिका अभी भी उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, करियर अवसरों और वीजा नीतियों के चलते मजबूत विकल्प बना हुआ है, लेकिन भारतीय छात्र अब पढाई के खर्च और वित्तीय मदद जैसे कारकों को प्राथमिकता दे रहे हैं।

सर्वे में 66 प्रतिशत छात्रों ने खर्च को सबसे बड़ी चिंता बताया, जबकि 47 प्रतिशत ने वीज़ा चुनौतियों, 43 प्रतिशत ने हाउसिंग खर्च और 39 प्रतिशत ने पार्ट-टाइम नौकरी के साथ पढ़ाई को चुनौतीपूर्ण माना। इसके अलावा, 55 प्रतिशत छात्रों ने कहा कि स्कॉलरशिप उपलब्धता से वे अपना डेस्टिनेशन बदल सकते हैं, जबकि 54 प्रतिशत ने पार्ट-टाइम वर्क के विकल्प को अहम माना। रिपोर्ट के अनुसार, 77 प्रतिशत भारतीय छात्र विदेश में पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य बेहतर करियर और आय की संभावनाएं मानते हैं। इन रुझानों के बीच, ऑस्ट्रेलिया की स्टूडेंट-फ्रेंडली नीतियां और शैक्षणिक प्रतिष्ठा उसे भारतीय छात्रों के लिए नई पसंदीदा मंज़िल बना रही हैं। अब यदि प्रधानमंत्री अल्बनीज , जीत के लिए भगवा थाम लिया था तो उन्हें भारतीय वोटरों का महत्त्व भी समझ लिया होगा जो आगे चल कर भारतीय क्षात्रों के लिए लाभ दायी होगा।

बम-गोलों से नहीं, पानी से जवाब दे रही भारत सरकार

आतंक से मुकाबला

संदीप सृजन

लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।

पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। इस हमले के जवाब में भारत सरकार ने सैन्य कार्रवाई के बजाय एक अनूठी और रणनीतिक नीति अपनाई, पाकिस्तान को पानी की आपूर्ति पर नियंत्रण। भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित करने का ऐलान किया, जिसे कई विशेषज्ञ एक 'जल युद्ध' की शुरुआत के रूप में देख रहे हैं। सिंधु जल संधि, जिसे 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में हस्ताक्षरित किया गया था, दोनों देशों के बीच जल बंटवारे का एक महत्वपूर्ण समझौता है। इस संधि के तहत, छह नदियों-सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, और सतलज-के जल को बांटा गया। पूर्वी नदियां (रावी, ब्यास, सतलज) भारत के नियंत्रण में दी गईं, जबकि पश्चिमी नदियां (सिंधु, झेलम, चिनाब) मुख्य रूप से पाकिस्तान के लिए निर्धारित की गईं। यह संधि दो युद्धों (1947 और 1965) के बावजूद दोनों देशों के बीच सहयोग का प्रतीक रही।

पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और कृषि के लिए सिंधु नदी प्रणाली अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह देश की 90 प्रतिशत से अधिक कृषि भूमि को सिंचित करती है और इसके बिना पाकिस्तान में खाद्य सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। दूसरी ओर, भारत, जो इन नदियों का ऊपरी हिस्सा नियंत्रित करता है, हमेशा से इस संधि का पालन करता रहा है, भले ही दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता रहा।

पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की जान गई, हमला पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठनों द्वारा किया गया। इस घटना के बाद भारत सरकार ने त्वरित और सख्त कदम उठाए। जहां पहले भारत ने उरी (2016) और पुलवामा (2019) हमलों के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे सैन्य कदम उठाए थे, इस बार उसने एक गैर-सैन्य, लेकिन रणनीतिक रूप से प्रभावी रास्ता चुना- पानी की आपूर्ति पर नियंत्रण। भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने की घोषणा की और कहा कि वह पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम, चिनाब) के पानी का अधिकतम उपयोग करेगा। जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि पाकिस्तान को एक बूंद पानी न मिले। इसके अलावा, भारत ने अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया, पाकिस्तानी राजनयिकों को निष्कासित किया, और भारतीय हवाई क्षेत्र में पाकिस्तानी उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया। ये कदम स्पष्ट रूप से यह संदेश देते हैं कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ कठोर और दीर्घकालिक नीतियां अपनाएगा।

पानी को हथियार बनाने की भारत की रणनीति का यह कदम कई मायनों में अभूतपूर्व है। परमाणु शक्ति संपन्न दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव से परमाणु युद्ध का खतरा बना रहता है। भारत ने इस जोखिम से बचने के लिए एक ऐसी रणनीति अपनाई, जो न केवल प्रभावी है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए भी स्वीकार्य हो सकती है। पानी को हथियार बनाना एक ऐसी रणनीति है, जो पाकिस्तान की आर्थिक और सामाजिक संरचना पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। पाकिस्तान पहले से ही जल संकट से जूझ रहा है। विश्व बैंक और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के अनुसार, पाकिस्तान दुनिया के सबसे अधिक जल-संकटग्रस्त देशों में से एक है। जनसंख्या वृद्धि, खराब जल प्रबंधन, और जलवायु परिवर्तन ने इस समस्या को और गंभीर बना दिया है। यदि भारत पश्चिमी नदियों के पानी को रोकता है या उसका मार्ग बदलता है, तो पाकिस्तान में कृषि, पेयजल आपूर्ति, और जलविद्युत उत्पादन पर गंभीर संकट आ सकता है। भारत की यह रणनीति कई स्तरों पर काम करती है। पानी की कमी से पाकिस्तान की कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा। यह देश की खाद्य सुरक्षा को खतरे में डालेगा और सामाजिक अशांति को बढ़ावा दे सकता है। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। पानी जैसे संसाधन का उपयोग करके भारत ने पाकिस्तान को बिना सैन्य टकराव के कठोर संदेश दिया है। यह कदम भारत के पड़ोसी देशों, विशेष रूप से चीन, को भी यह संदेश देता है कि भारत अपने संसाधनों का उपयोग रणनीतिक रूप से करने में सक्षम है।

सिंधु, झेलम, और चिनाब नदियां भारत के नियंत्रण में हैं, और इनका पानी पाकिस्तान में बहता है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि पानी को पूरी तरह रोकना तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण है। भारत के पास वर्तमान में पर्याप्त बांध और जलाशय नहीं हैं जो पश्चिमी नदियों के विशाल जल प्रवाह को रोक सकें। आजतक की ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस टीम के अनुसार, पाकिस्तान में बहने वाले पानी को रोकने के लिए भारत को भाखड़ा नांगल जैसे 22 बड़े बांधों की आवश्यकता होगी। हालांकि, भारत मौजूदा बुनियादी ढांचे का उपयोग करके पानी के प्रवाह को सीमित कर सकता है। गर्मी के मौसम में, जब पाकिस्तान में पानी की मांग सबसे अधिक होती है, भारत पानी की मात्रा को कम कर सकता है। इसके अलावा, भारत नई परियोजनाओं पर काम शुरू कर सकता है, जैसे कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में जलाशयों का निर्माण, जो लंबी अवधि में पानी के उपयोग को बढ़ाएगा।

भारत का यह कदम अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश है। विश्व बैंक, जो इस संधि का मध्यस्थ है, और संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन इस स्थिति पर नजर रख रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत के कदम को अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है और विश्व बैंक से हस्तक्षेप की मांग की है। हालांकि, भारत का तर्क है कि पहलगाम हमले जैसे आतंकी कृत्यों के बाद वह संधि का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन, और अन्य पश्चिमी देशों ने पहलगाम हमले की निंदा की है और भारत को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन दिया है। तुलसी गबार्ड जैसे अमेरिकी नेताओं ने भारत को आतंकियों को न्याय के कटघरे में लाने में मदद का आश्वासन दिया है। इससे भारत की स्थिति कूटनीतिक रूप से मजबूत होती है।

भारत का यह कदम दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा सकता है। क्योंकि पानी की कमी से पाकिस्तान की पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था और खराब हो सकती है। इससे सामाजिक अशांति और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ सकती है। हालांकि दोनों देश परमाणु युद्ध से बचना चाहते हैं, सीमा पर छोटे-मोटे संघर्ष बढ़ सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण दोनों देश बातचीत की मेज पर आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाने होंगे। भारत सरकार का सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला एक साहसिक और रणनीतिक कदम है, जो बम-गोलों के बजाय पानी को हथियार बनाता है। यह कदम न केवल पाकिस्तान को आर्थिक और सामाजिक दबाव में डाल सकता है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को भी मजबूत करता है। हालांकि, इस रणनीति के साथ कई चुनौतियां भी जुड़ी हैं, जैसे कि तकनीकी सीमाएं और अंतरराष्ट्रीय दबाव। भविष्य में, यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत इस रणनीति को कैसे लागू करता है और पाकिस्तान इसका जवाब कैसे देता है। एक बात स्पष्ट है-भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में नए और प्रभावी तरीके अपनाने से नहीं हिचकिचाएगा।

संवेदना की तूलिका से यथार्थ का चित्रण

विमोचन आज

मांडवी सिंह

समीक्षक

संवेदना और यथार्थ के बीच का भोगा हुआ दर्द जब सामाजिक सरोकार की गहन वेदना से छटपटाता है तब दो पाटन के बीच जैसी कृति पाठकों के समक्ष अपनी पूर्णता के साथ उपस्थित होती है।

प्रेमचंद गुप्त जी द्वारा लिखित कविता संग्रह एक भावपूर्ण और विचारोत्तेजक कविताओं की सुंदर रंगोली है, जिसमें कवि ने जीवन और समाज के विभिन्न पहलुओं को बहुत बारीकी से स्पर्श किया है। जैसे -

देखो ना
तकनीक के इस महीने धागे ने
जकड़ रखा है पोते - पोतियों को
कभी जाने ही नहीं देता
उन्हें परीलोक में,
कितना नीरस है यह यथार्थ।

आपकी कविताएं जीवन की वास्तविकता को दर्शाती है जिसमें सामाजिक मुद्दे ,जीवन की चुनौतियां, प्रेम ,पर्यावरण रिश्तों के बदलते परिदृश्य, स्वार्थपरता,बढ़ती आकांक्षा के बीच विलुप्त होता बचपन ,जवानी ,और बुढ़ापा इत्यादि जैसे ज्वलंत और संवेदनात्मक विषयों पर लिखा हुआ सच पाठकों को स्वयं का भोगा हुआ दर्द दिखाई देने लगता है ।अपराजिता कविता में स्त्री के संपूर्ण व्यक्तित्व का चित्रण करते हुए गुप्त जी लिखते हैं- व्यष्टि से समष्टि होती एक आदत औरत ।

वही दिव्यत्व शीर्षक कविता में 'माटी की मूरत था पहले कोई तरल सोख लेता था ।' मानव और मशीनी मानव के बीच का अद्भुत अंतर दर्शाता है । कहीं-कहीं पर कवि भ्रष्टाचार, कर्महीनता और छद्म से टूटकर लिखता है,

मुझे क्यों समझ नहीं आता
अंक गणित जीवन का।

इसके अलावा दर्द न जाने कोई, बूंद से समुद्र तक ,तलवे का कांटा ,लोग कहते हैं, रहिमन पानी राखिए ,जीवन कथा, तुम्हारा होना ,संवेदना इत्यादि कविताएं अत्यंत मर्मस्पर्शी हैं। अन्य कवियों की भावनाओं से इतर बेटी बचाओ कविता में समाज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर गुप्त जी ने ऐसा प्रहार किया है कि मन दूर तलक सोचने को विवश हो जाता है। कविताओं में भावनात्मक अभिव्यक्ति का उपयोग करके सामाजिक मुद्दों को उजागर किया गया है कविताएं सामाजिक परिवर्तन की अपील करती हैं। जीवन की सच्चाई के प्रति संवेदनशील बनाती है। भाषा सरल, सहज और बोधगम्य है। कविताओं का कलेवर कहीं-कहीं विस्तृत हो गया है परंतु कहीं चार पंक्तियों में गागर में सागर समा गया है जैसे-

ऐसा नहीं है मां कि
मुझे लिखना नहीं आता
तुम हो कि शब्दों में समाती ही नहीं।

इस प्रकार स्वागत वसंत, मित्र हिमालय, सिंधु बिंदु, आई होली, नदी को शिकायत है,आषाढ़ का प्रथम दिन इत्यादि कविताओं के माध्यम से कवि ने प्रेम, प्रकृति के बहाने सामाजिक मुद्दों पर अनुभूतिजन्य बाण चलाया है। 152 पृष्ठ पर 73 छंद मुक्त कविताओं की सुंदर फुलवारी अपने रंग-बिरंगे फूलों की खुशबू और कलेवर के साथ पाठकों को अपने सुगंध से सुरभित करने को तैयार है। कविता संग्रह सुंदर आवरण पृष्ठ के साथ बहुत ही उपयोगी और आकर्षक है।

पुस्तक का नाम - दो पाटन के बीच
कवि - प्रेमचंद गुप्त

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा 'उरतृप्त'

लेखक व्यंग्यकार हैं।

चाय, चमचा और चुटकी नमक

कहते हैं कि अगर आपकी चाय में नमक पड़ जाए तो या तो आप बहुत बड़े नेता बनने वाले हैं, या फिर किसी ने आपके जीवन की मिठास में सेंध लगा दी है। मेरे मोहल्ले के शशिकांत जी ने दोनों कर डाले - नेता भी बन गए और मोहल्ले की बहुओं की आँखों से गंगाजल भी बहवा दिया। वो जब सुबह-सुबह अपनी बीवी को 'गुड मॉर्निंग' कहते थे तो बीवी नमकदानी फेंक देती थी -तुमसे तो गुडनाइट ही बेहतर है।- मोहल्ले में कोई मरता, तो शशिकांत जी सांत्वना देने से पहले पूछते, -मौत अचानक हुई या रूटीन की?- उनके चेहरे पर हमेशा एक स्थायी व्यंग्य होता - मानो जिंदगी को उन्होंने ईएमआई पर ले रखा हो।

पिछले महीने उन्होंने समाज सेवा का नया स्टार्टअप खोला - 'चाय विद चुटकी'। उद्देश्य था -एक कप में समाज की सारी समस्याओं को घोलना और फिर उसे गर्मागरम परोस देना। लेकिन पहले ही दिन समस्या घुल नहीं पाई, चाय में नमक घुल गया। वो चाय पीने वालों से बोले, 'भाइयों और बहनों, यह चाय नहीं, व्यवस्था का घड़ा है - पी जाओ, तभी तो सुधार होगा।- लोगों ने पिया... और उल्टी भी की। पर शशिकांत जी मुस्कराए -क्रांति ऐसे ही होती है।'

हर मोहल्ले में एक चमचा होता है। पर शशिकांत जी के यहाँ तो चमचों की पूरी पंचायत थी - रामलाल, जमुना प्रसाद, और विमलेश। ये लोग हर बात पर ताली बजाते -वाह साहब ! आपने तो गधे को भी घोड़ा बना दिया !- शशिकांत जी मुस्कराते, -सही पकड़े हैं।- उन्होंने हर समस्या का हल चाय में ढूंढा - बेरोजगारी? एक चाय दो, नौकरी लग जाएगी। गड्ढों वाली सड़क? चाय पर चर्चा कर लो, सड़क तो न बदलेगी, मन जरूर बदल जाएगा। एक बार तो उन्होंने कहा -जीडीपी गिर रही है? कोई बात नहीं, कप तो उठ रहा है न? और पूरा मोहल्ला हँसते-हँसते रो पड़ा।

घर में शशिकांत जी के बच्चे उन्हें 'पापा' नहीं, 'पब्लिक स्पीकर' कहते थे। जब भी उनकी बेटी उनसे नए जूते मांगती, वो कहते -बेटी, असली सुंदरता आत्मा की होती है, पैर की नहीं। बेटे ने एक बार कहा, पापा, स्कूल में सब मेरा मज़ाक उड़ाते हैं। जवाब मिला -तो क्या हुआ? मैं भी नेता बना हूं, मेरा भी मज़ाक उड़ता है, फिर भी जनता मुझे वोट देती है। घर की रसोई में नमक खत्म हो जाए, तो शशिकांत जी कहते -चलो बेटा, समाज को सुधारने चले चलते हैं, वापसी में नमक भी ले आएंगे।

उनकी पत्नी - गीता देवी- अब तक तो भगवद्गीता की भी सारी शिक्षाएँ भूल चुकी थीं। कहती थीं, -जैसे कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, वैसे ही मैं भी हर रोज इन्हें समझाती हूं - लेकिन ये महाभारत तो क्या, महाअव्यवस्था रचकर ही दम लेते हैं। एक दिन गीता देवी ने गुस्से में कहा, अब बस ! या तो तुम, या चाय की दुकान। शशिकांत जी बोले तो फिर मैं चाय को चुनता हूं। और मोहल्ले में पहली बार तालियाँ नहीं, सिसकियाँ सुनाई दीं। उनकी दुकान पर रोज़ नए-नए नारे लगते देश बदलेगा, जब चाय उबलेगा ! लेकिन धीरे-धीरे उनकी चाय में न नशा रहा, न चर्चा। ग्राहक कम हुए, और व्यंग्य ज्यादा। लोग कहते -शशिकांत जी की चाय पीने से पेट तो नहीं भरता, पर दुख जरूर उबल जाता है। एक दिन एक बूढ़ी अम्मा आई, चाय पी और बोलीं -बेटा, यह चाय नहीं, यह तो मेरी बुढ़ापे की दवा बन गई है। और वहीं कुर्सी पर बैठकर रो पड़ीं। शशिकांत जी ने उन्हें देखा और पहली बार उनकी आँखों में व्यंग्य नहीं, पानी था।

समाज सुधारते-सुधारते शशिकांत जी अब खुद समाज की चाय बन चुके थे जिसे कोई पीता नहीं, सिर्फ छोड़ देता है। एक दिन दुकान बंद मिली। दरवाज़े पर लिखा था -अब न चाय बचेगी, न चुटकी नमक। समाज में सब कुछ नमकीन है, पर दिल अब बेस्वाद हो चुका है। मोहल्ला ठहरा, लोग ठिठके और पहली बार, उनकी गैर-मौजूदगी में शोर नहीं, सन्नाटा था।शशिकांत जी अब नहीं हैं। कहते हैं, अंतिम समय में उन्होंने कहा मेरी अस्थियाँ किसी सरकारी गड्ढे में बहा देना... कम से कम वहाँ कुछ भराव तो होगा। मोहल्ले में उनकी याद में एक पत्थर रखा गया उस पर लिखा है यहाँ वो आदमी बैठता था, जो समाज को चाय के प्याले में घोलकर पी जाना चाहता था।हर शाम अब वहाँ लोग चुपचाप बैठते हैं बिना चाय, बिना नमक पर आँखों में नमी, और दिल में 'उरतृप्त' पीड़ा लिए हुए।

जाति जनगणना और पसमांदा मुसलमानों की सामाजिक स्थिति

भारत में मुस्लिम समुदाय की जटिल स्थिति है। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की कुल जनसंख्या का 14.2 प्रतिशत हिस्सा मुसलमानों का है, जो लगभग 18-20 करोड़ के बीच है। भारत में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी निवास करती है, इसके बावजूद यह एक अल्पसंख्यक समुदाय है। मुसलमानों को शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और धार्मिक भेदभाव जैसी कई सामाजिक व आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सांप्रदायिक हिंसा और सामाजिक असमानता की घटनाएं इस समुदाय के भीतर गहराई से महसूस की जाती हैं। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता और समानता का अधिकार प्रदान करता है, जिससे मुसलमानों को भी मौलिक अधिकार प्राप्त हैं।

सामयिक

अरूण कुमार डनायक

लेखक गांधी विचार अध्येता है।

भारत एक बार फिर एक ऐतिहासिक पहल की ओर अग्रसर है। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि आगामी जनगणना में जातिगत आंकड़े भी संकलित किए जाएंगे। वर्ष 1931 के बाद यह पहली बार होगा जब जाति आधारित जनगणना की जाएगी। हालांकि 2011 में हुई जनगणना के बाद सामाजिक आर्थिक आधार पर जातियों की गणना हुई थी पर इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किये गए। 94 वर्षों के बाद यह कदम सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक निर्णायक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है तथा सत्ता पक्ष और विपक्ष में इसका श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। भाजपा नेताओं के बयानों और मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर, कुछ मुस्लिम समूहों को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, केंद्र और राज्य की पिछड़ा वर्ग सूची में जाति जनगणना के तहत गिना जा सकता है। आगामी जनगणना में पसमांदा मुस्लिमों को ओबीसी श्रेणी में शामिल किए जाने की संभावना है।

भारत में मुस्लिम समुदाय की जटिल स्थिति है। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की कुल जनसंख्या का 14.2 प्रतिशत हिस्सा मुसलमानों का है, जो लगभग 18-20 करोड़ के बीच है। भारत में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी निवास करती है, इसके बावजूद यह एक अल्पसंख्यक समुदाय है। मुसलमानों को शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और धार्मिक भेदभाव जैसी कई सामाजिक व आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सांप्रदायिक हिंसा और सामाजिक असमानता की घटनाएं इस समुदाय के भीतर गहराई से महसूस की जाती हैं। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता और समानता का अधिकार प्रदान करता है, जिससे मुसलमानों को भी मौलिक अधिकार प्राप्त हैं।

इस्लामिक मान्यताओं में जातिगत भेदभाव की मनाही है, फिर भी भारतीय उपमहाद्वीप में मुसलमानों के भीतर भी जाति आधारित संरचना व्याप्त है। भारतीय मुस्लिम समाज को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है - अशरफ: सैयद, शेख, पठान, मुगल आदि विदेशी मूल के या उच्च हिंदू जातियों से धर्मांतरित हुए उच्च वर्गीय मुसलमान। अजलाफ : ये मध्यवर्ती जातियों से धर्मांतरित हैं और पारंपरिक रूप से 'स्वच्छ' व्यवसायों में संलग्न रहे हैं। अरज़ाल: ये सबसे निचली श्रेणी माने जाते हैं और 'अछूत' समझे जाने वाले कार्य करते हैं ।

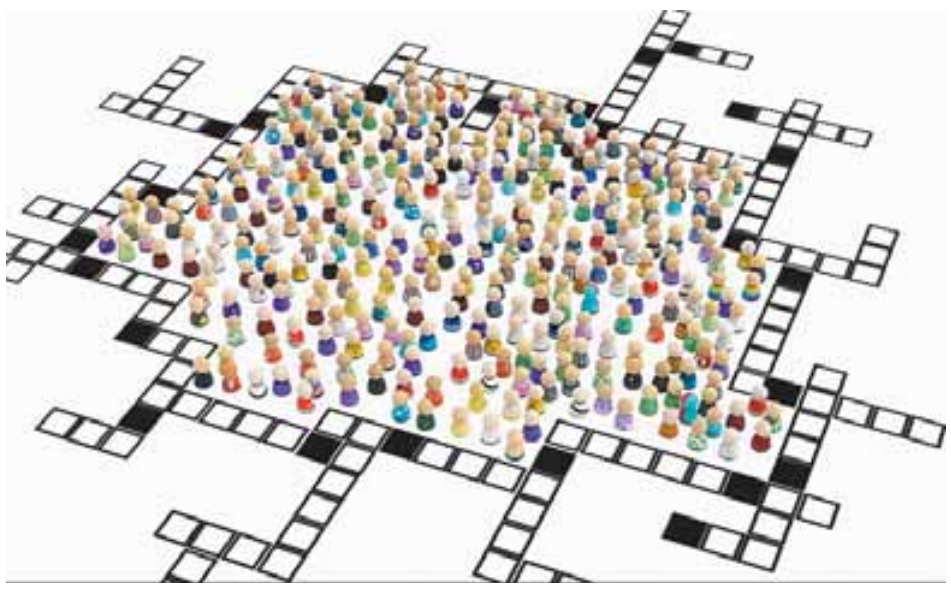

अजलाफ और अरज़ाल मुसलमानों के सामाजिक-सांस्कृतिक-आर्थिक पिछड़ेपन को संबोधित करने वाला 'पसमांदा' फारसी शब्द है, जिसका अर्थ है पीछे छूटे हुए। स्वतंत्रता से पहले पसमांदा आंदोलन के प्रमुख नेता अब्दुल कय्यूम अंसारी और मौलाना अली हुसैन असीम बिहारी थे, जो जुलाहा (बुनकर) समुदाय से थे। इन्होंने 1910 के बाद शुरू हुए इस सुधारवादी आंदोलन में मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक राजनीति और उसके सभी मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व के दावे का विरोध किया। फिर इस शब्द को 1998 में अली अनवर अंसारी द्वारा पहली बार राजनीतिक रूप से प्रयोग में लाया गया जब उन्होंने पसमांदा मुस्लिम महाज की स्थापना की।

सच्चर समिति (2006) और रंगनाथ मिश्रा आयोग (2007) ने भी स्वीकार किया कि मुसलमानों के भीतर जाति आधारित भेदभाव मौजूद है। सच्चर समिति की रिपोर्ट के अनुसार, मुसलमानों में लगभग 40 प्रतिशत ओबीसी और एससी/एसटी श्रेणियों से आते हैं, जबकि कई पसमांदा कार्यकर्ता इस आंकड़े को 80-85 प्रतिशत तक मानते हैं।

पसमांदा समुदाय का दावा है कि उनकी संख्या अधिक होने के बावजूद राजनीतिक, शैक्षिक और आर्थिक प्रतिनिधित्व में उनकी भागीदारी नगण्य है। उनकी प्रमुख मांगें हैं- जातिगत जनगणना में पसमांदा मुसलमानों को स्पष्ट रूप से अत्यंत पिछड़ा वर्ग की श्रेणी दर्ज करना, कारीगरों व कृषि मजदूरों और शिल्पकारों को सरकारी सहायता प्रदान करना, मुस्लिम समाज के भीतर संसाधनों की असमान वितरण प्रणाली को समाप्त करना। मेव सहित दलित मुस्लिम समुदायों की अनुसूचित जाति (एससी) दर्जे की उनकी मांग अनुसूचित जाति आदेश, 1950 के अनुसार संविधान सम्मत नहीं है। यह आदेश मूल रूप से केवल हिंदुओं को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करता था, अन्य धर्मों के दलितों को इससे बाहर रखा गया था। बाद में 1956 और 1990 में संशोधनों के माध्यम से सिखों और बौद्धों को भी इस श्रेणी में शामिल किया गया। तेलंगाना और बिहार की जातिगत जनगणनाओं में यह स्पष्ट हुआ कि क्रमश: 81 प्रतिशत और 73 प्रतिशत मुसलमान पसमांदा श्रेणी में आते हैं। इस जनगणना से पसमांदा मुसलमानों के सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन को मान्यता मिलने की संभावना है, जो नीति निर्धारण और आरक्षण व्यवस्था को अधिक न्यायपूर्ण बनाने में सहायक होगा।

कुछ मुस्लिम संगठनों और नेताओं को यह आशंका है कि पसमांदा मुसलमानों को अलग श्रेणी में दर्ज करना समुदाय को विभाजित करने का प्रयास हो सकता है। उनका कहना है कि यदि यह प्रक्रिया पारदर्शी और न्यायसंगत नहीं हुई तो इससे मुस्लिम समाज के भीतर और विभाजन पैदा हो सकता है। कुछ हिंदू संगठनों का तर्क है कि आज़ादी के समय हैदराबाद, भोपाल, रामपुर जैसी 10-12 रियासतों में मुस्लिम शासक थे, इसलिए मुस्लिम समुदाय के पिछड़ेपन का दावा अनुचित है। उनका मानना है कि इन रियासतों में मुस्लिमों की सत्ता और प्रभाव को देखते हुए, उनके सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन का तर्क तथ्यात्मक रूप से कमजोर है।

जाति जनगणना एक अत्यंत आवश्यक कदम है जो 1931 के बाद भारत के विविध सामाजिक ताने-बाने को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। पसमांदा मुसलमानों की गिनती और पहचान यदि सही ढंग से की जाती है, तो यह उनके ऐतिहासिक वंचन को पहचानने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास होगा। यह न केवल मुस्लिम समाज के भीतर समावेशी विकास को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि भारत में सभी कमजोर वर्गों के लिए एक समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। लेकिन मुस्लिम समुदाय की प्रमुख समस्याओं का समाधान जातिगत जनगणना में नहीं बल्कि गांधी जी के विचारों के अनुसार उनकी शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने, कार्यपालिका और विधायिका में उचित प्रतिनिधित्व देने और सामाजिक कुप्रथाओं को समाप्त करने में निहित है। इसके अतिरिक्त, रूढ़िवादी परंपराओं जैसे बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, तलाक, पुरानी उत्तराधिकार प्रणाली, महिलाओं की शिक्षा, रोजगार व संपत्ति में सीमित हिस्सेदारी भी समुदाय की प्रगति में बाधक हैं। इन सामाजिक कुरीतियों को दूर करके और समावेशी शिक्षा व आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देकर ही मुस्लिम समुदाय कासशक्तिकरण संभव है।

और भी निहितार्थ हैं जाति-जनगणना के

राजनीतिक दल हैं तो उन्हें राजनीति ही करना है, नाम चाहे कुछ भी दे दिया जाए । इन रास्तों पर किसीसे नैतिकता और नीति की उम्मीद करना बेकार है। भाजपा इस मामले में बहुत सावधान और जागरुक पार्टी है। जाति जनगणना की मांग बहुत समय से की जा रही थी और खुद भाजपा उसे नकार रही थी। फिर अचानक क्या हुआ जो उसने इसकी घोषणा कर दी! बदले माहौल से हमें इसका अंदाज हो सकता है। सारे दलों का ध्यान पहलगाम से हटकर अब जाति जनगणना के क्रेडिट वार में बदल गया है। युद्ध के लिए चीखते मीडिया में अब आरक्षण को लेकर के चर्चा जोरों पर है। आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत रहेगी या बढ़ेगी। उच्च जातियों का क्या होगा। वाट्सएप मेसेज दौड़ रहे हैं कि गणना के समय अपना वर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यदि) ही लिखवाएं ताकि संख्या बढ़ कर दिखे । मुद्दा गरम होता जा रहा है। लोग धीरे-धीरे इससे जुड़ते जा रहे हैं और पिछला कुछ भूलते भी जा रहे हैं। आगे चुनाव में किस पार्टी को कितना लाभ मिलेगा इस पर भी कयास चल रहे हैं।

दृष्टिकोण

जवाहर चौधरी

लेखक स्तंभकार हैं।

मजबूरी का नाम इन दोनों जाति जनगणना है। इसे मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा रहा है। लेकिन मास्टर कौन है इस पर राय अलग-अलग है। हर पार्टी का दावा है और हर एक को इससे उम्मीद भी है। लग रहा है कि जनगणना द्रोपदी है। पहलगाम की घटना के बीच जब सारा देश एक मत होकर आतंकवादियों से बदला लेने की इच्छा व्यक्त कर रहा था अचानक जाति जनगणना की घोषणा हो जाती है ! किसी शायर ने कहा है कि 'कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता'। यों देखा जाए तो युद्ध किसी समस्या का हल भी नहीं है। जो भी कदम उठाने जाएं बहुत सोच समझ कर उठाया जाना चाहिए। लगता है कि सरकार इस मामले में ठीक ही कर रही है। आतंकवाद को समाप्त करना तमाम देशों की संयुक्त इच्छा से संभव है। खैर फिलहाल जाति जनगणना पर रुकते हैं।

राजनीतिक दल हैं तो उन्हें राजनीति ही करना है, नाम चाहे कुछ भी दे दिया जाए । इन रास्तों पर किसीसे नैतिकता और नीति की उम्मीद करना बेकार है। भाजपा इस मामले में बहुत सावधान और जागरुक पार्टी है। जाति जनगणना की मांग बहुत समय से की जा रही थी और खुद भाजपा उसे नकार रही थी। फिर अचानक क्या हुआ जो उसने इसकी घोषणा कर दी! बदले माहौल से हमें इसका अंदाज हो सकता है। सारे दलों का ध्यान पहलगाम से हटकर अब जाति जनगणना के क्रेडिट वार में बदल गया है। युद्ध के लिए चीखते मीडिया में अब आरक्षण को लेकर के चर्चा जोरों पर है। आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत रहेगी या बढ़ेगी। उच्च जातियों का क्या होगा। वाट्सएप मेसेज दौड़ रहे हैं कि गणना के समय अपना वर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यदि) ही लिखवाएं ताकि संख्या बढ़ कर दिखे । मुद्दा गरम होता जा रहा है। लोग धीरे-धीरे इससे जुड़ते जा रहे हैं और पिछला कुछ भूलते भी जा रहे हैं। आगे चुनाव में किस पार्टी को कितना लाभ मिलेगा इस पर भी कयास चल रहे हैं। आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव है और तेजस्वी व नीतीश कुमार इस मुद्दे को लेकर के महामुखर हैं। इधर कहा जा रहा है कि भाजपा की पैठ ओबीसी में हो गई है और अब वह केवल ब्राह्मण बनियों की पार्टी नहीं है। दलित समर्थन के लिए सभी दलों में खींचतान चल रही है। यों लग रहा है मोहल्ले में पानी का टैंकर आया है और दबंग पाइप डालकर ज्यादा से ज्यादा पानी अपने हिस्से में खींच लेना चाह रहे हैं।

यदि ठहर कर देखें तो जाति जनगणना केवल राजनीतिक मसला नहीं है। इससे अन्य बहुत सी जरूरी बातों का पता चलेगा। शिक्षा और रोजगार को लेकर देश की चिंता बड़ी है। विभिन्न जातियों में कितने लोग शिक्षित हैं और कितने इनमें बेरोजगार हैं। महिलाओं की शिक्षा और रोजगार की स्थिति को जानना भी जरूरी है। नौकरियों में और व्यवसाय में कौन लोग किसी संख्या में कार्यरत है। सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों की स्थिति क्या है। सरकारी नौकरियों और उच्च व्यवसाय में कौन कौन लोग लगे हुए हैं। सामाजिक परिदृश्य भी से साफ होगा। कितने लोगों के पास आवास और अन्य सुविधाएं हैं या नहीं हैं। स्त्रियों में अविवाहित, विधवाएं और बेसहारा, अनाथ बच्चों की सही सही संख्या पता चल पाएगी। जातियों में ग्रामीण नगरीय और संयुक्त एकल परिवारों का सही आंकड़ा हमारे सामने होगा। जातियों के जीवन स्तर और आय वर्ग का भी हमें पता चलेगा। देश में करोड़ों रूपयों की योजनाएं बनती हैं लेकिन जमीनी स्तर के आंकड़ों के अभाव में योजनाएँ पूरा लाभ नहीं दे पाती हैं। अनुमानों के आधार पर क्रियान्वित योजनाओं का लाभ लेने से वे लोग अक्सर वंचित रह जाते हैं जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है। जाति-जनगणना से सही लाभार्थियों के मामले में स्थिति साफ होगी।

जैसा की आशंका की जा रही थी कि जाति जनगणना से हिंदू समाज बँट जाएगा। नारे भी दिए गए कि बँटोगे तो कटोगे या एक रहोगे तो सेफ रहोगे। हकीकत तो यह है कि सदियों से जाति व्यवस्था के कारण जितना और जिस तरह से बँट सकता है उतना बँटा हुआ है समाज। अभी भी जातियों की गौरव यात्राएं या रैलियाँ निकलती हैं । अभी भी जातियों रोटी बेटी व्यवहार सुगम नहीं है । मंदिरों में प्रवेश से रोकने की घटनाएँ आए दिन होती हैं । बावजूद इसके समाज अनेक स्तरों पर एक दिखाई देता है और मजबूत है। जाति जनगणना से अब और बँटना संभव नहीं है । सभी जातियां एक दूसरे की वास्तविक स्थिति को जानेंगी तो करीब आएंगी । स्थितियां ऐसी बनेगी की उच्च वर्ण को थोड़ा उदार होना पड़ेगा। अन्य वर्णों को भी अपनी वास्तविक स्थिति के अनुसार समायोजन करना होगा। शुरुआती हलचल के बाद वास्तविक स्थिति के अनुसार जातियों में परस्पर समझ का वातावरण बनेगा। आरक्षण का मामला केवल नौकरी के संदर्भ में है। लेकिन नौकरियां कितनी है यह भी सब जानते हैं। आंकड़े यदि साफ तौर पर उपलब्ध होंगे तो रोजगार के अन्य अवसरों की ओर भी आकर्षण बढ़ेगा। जाति जनगणना के शुरुआती गुबार को यदि ठीक से बैठ जाने दिया जाएगा तो इसके लाभ भी हमें दिखाई दे सकेंगे ।

यहां तो बस इस बात में मगन हैं कि क्या कर लिया

विचार

विवेक कुमार मिश्र

लेखक हिंदी के प्रोफेसर हैं।

जिंदगी जीने के लिए मिली है और जिंदगी को जीना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। जिंदगी को जीना सीखें । लोग जीने की जगह बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिसका जीवनशैली से या कहें जीवनचर्या से कोई लेना-देना नहीं होता है । न जाने कितने दबाव और तनाव को लेकर ऐसे जीते चलते हैं कि यहीं सबकुछ हो...इसके अलावा जीवन में कुछ और हो ही नहीं। भला इस तरह जीने का कोई अर्थ है कि जहां अपना जीवन न होकर केवल यहीं बात होती रहती है कि कौन कहां है ? क्या कर रहा है ? किसी को स्वयं की की चिंता नहीं रहती सब बस यहीं देखने में व्यस्त रहते हैं कि दूसरे ने क्या कहा ? क्यों कहा और कौन किसके पास बैठा है । ये मसले इतने गंभीर होते हैं कि दिन रात आदमी इस फितरत में लगा रहता है कि वह क्या ऐसा कर दें कि हर आदमी उससे खुश रहे पर यह भी तय है कि आप स्वयं तो खुश रह सकते हैं पर सबको खुश रखने की कोशिश में हो सकता है कि आप कहीं के भी न रहे। यह दुनिया इतनी आसान नहीं है कि हर कोई हर बात मान ही लें या जैसा आप सोचते हैं वैसा ही सामने वाला भी सोचे। दुनिया अक्सर एक जटिल संभावनाओं के बीच काम करने वाले लोगों की होती है। यहां कुछ भी आसान नहीं होता। आसान बनाना पड़ता है। आपको यह देखना होता है कि किसी भी कार्य को आप कैसे कर सकते हैं। उस कार्य में आपकी स्टाइल कहां है और कैसे आ सकती है। यह तभी संभव हो पाता है जब उस कार्य के साथ आपका मन लगा हो, उस कार्य को आप मन से कर रहे हों। अक्सर आदमी किसी भी कार्य की शुरुआत बिना मन के करता है और जब उसे उस कार्य में सिद्धि नहीं मिलती तो वह दुनिया भर की अनावश्यक बातों को लेकर आता है कि मैं क्या करूं ? ऐसा है तो वैसा है और फिर सबसे बड़ा दोष किस्मत पर डाल कर बैठ जाता है। जबकि होना यह चाहिए कि आदमी जो भी कार्य करें उसमें अपना सबकुछ लगा दें, पूरा मन लगाकर कार्य करें। जब आप समर्पित होकर कार्य करते हैं तो फिर कैसा भी कठिन कार्य क्यों न हो उसे आप सफलतापूर्वक संपन्न कर लेते हैं। जो लोग अपने कार्य में सफल होते हैं वे लोग सिर्फ इसी बात में अन्य से अलग होते हैं कि उस कार्य के प्रति अपने आपको पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं। उस कार्य की विषयवस्तु में गहराई से जाते हैं और उसे अपना कार्य समझकर इस तरह से करते हैं कि कार्य पूरा हो जाएं। चीजें कैसे आपके हिसाब से हों या इस संसार में आप क्या करें कि आप अपने मनपसंद कार्य भी कर लें और दुनिया को भी उसके हिसाब किताब के साथ देखते रहें। इस तरह से जब लोग चलते हैं तो न तो ठीक से अपने बारे में जान पाते हैं न ही अपने आसपास के बारे में जानते हैं। यहां बस सबकी एक ही चिंता रहती है कि दूसरे कैसे हैं और कौन क्या कर रहा है ? जबकि इसका कोई अर्थ नहीं होता। आप अपने लिए क्या सोच रहे हैं और अन्य के लिए क्या कर रहे हैं । यहां जिंदगी का जो अर्थ है वह एक दूसरे की कमी ही देखने में लगी रहती है। आदमी यह नहीं सोचता कि वह क्या और क्यों कर रहा है वह बस इसलिए चलता है कि और लोग भी उसी दिशा में जा रहे थे तो वह भी चल दिया है।

दूसरों की दुनिया में मतलब रखने वाले अक्सर जिंदगी को जीते नहीं बल्कि इसी उधेड़बुन में पड़े रहते हैं कि कौन कौन कहां चला गया? किसने क्या हासिल कर लिया और वह यहीं कैसे रह गया। उसके इसी तरह होने में कोई और कारक नहीं है पर वह पूरी दुनिया को ही अपने विरोध में रखकर देखता है और एक काल्पनिक विरोध सामने खड़ा कर लेता है। तभी उसके मन में तरह तरह से सवाल आता रहता है । वह कौन है और क्यों इसी दुनिया में पड़ा है तो? इसका कोई उत्तर नहीं मिलता। सब लोग बस चलताऊ जवाब देते रहते हैं कि यह हो सकता है तो यह हो सकता है। इस तरह के सवालों में अक्सर लोग उलझे रहते हैं कि कौन कहां आ रहा है कहां जा रहा है ? दुनिया में कौन किसके आगे पीछे घूम रहा है और अपने मन मस्तिष्क में सुबह से शाम तक अनावश्यक बातों का बोझ भर रहा है। आपने देखा होगा कि किसी को भी इस बात की चिंता नहीं होती कि उसे क्या करना है? उसे क्या करना चाहिए? वह इस चिंता में ही रात दिन एक किए रहता है कि यदि वह पहाड़ जा रहा है तो मैं उससे भला कम कैसे रहूं । मैं पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाऊंगा। ज्यादातर लोग दूसरे के चक्कर में पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाने की ज़िद में रहते हैं और बहुधा गिर जाते हैं या अपना वीपी बढ़ा लेते हैं । आपको यदि संसार को सही ढ़ंग से समझना है तो अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाएं और आनंद के साथ जीना सीखें। कुछ सूत्र जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं उसे अपने साथ रखें। अपनी कार्य संस्कृति का हिस्सा बनाएं -

1. अपने उपर भरोसा रखें, यह विश्वास बनाते चलें कि कुछ भी हो यह कार्य मैं कर लूंगा । इसी कार्य के लिए मैं बना हूं ।
2. जब कदम बढ़ाएं तो उसे रोकें मत, यदि कदम बढ़ा दिया है तो अगला कदम भी बढ़ाते चलें। एक दिशा में चले गए अनगिनत कदम ही सफलता की चोटी पर बिठाते हैं।
3. अपने कार्य के इतिहास को समझें। आपसे पहले अन्य लोगों ने कैसे यह सब किया। अपने कार्य करने के तरीके में कमी कहां रह गई जो नहीं रहना चाहिए। यह जानना होगा।
4. अपने कार्य के साहित्य को ध्यान में रखकर चलें। अन्य सफल लोगों की जीवन कथा को पढ़ते चलें। उनसे सीखें।
5. लगातार नये संदर्भ और न ई सूचनाओं की जानकारी लेते रहे। जो आज ठीक है जरूरी नहीं कि वह कल भी ठीक हो।
6. हमेशा एक विकल्प लेकर चलें। एक प्लान फेल हो जाता है तो घबराएं नहीं दूसरे प्लान को लेकर आगे बढ़े।
7. हर कदम को गंभीरता से आगे बढ़ाए । आपके उपर जो भरोसा रखता है उसके भरोसे को न तोड़ें। विश्वास रखने का कारण बने तभी सफलता मिलेगी।
8. अपने समय की वास्तविकता को पहचाने । लोग क्या सोचते हैं, लोगों की जरूरत क्या है इसे पहचानकर ही कार्य किया जा सकता है।
9. सफलता और सार्थकता को अपना मिशन बनाते हुए चलें । आप अकेले नहीं हैं आप जैसे अनेकों लोग हैं जो चलते हैं और सफल होते हैं । जो सफल होते हैं उनमें कुछ ऐसा खास होता है जो औरों से उन्हें अलग करता है । इसी बात को समझ कर आप अपनी दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं।

दुनिया खूबसूरत है और इसे अपने हिसाब से अपने मनपसंद कार्य से आप और खूबसूरत बना सकते हैं। अपनी स्थितियों में ही दुनिया को सुंदर और खूबसूरत बनाता हुआ आदमी ही सबसे अच्छा आदमी लगता है। देखता हूं कि एक आदमी को गाने का शौक है तो वह मन से गाना गाता है और अपनी दुनिया में आनंद के साथ खो जाता है। ऐसी जगह पर जाकर आपको एक दिव्यता की अनुभूति होगी यहां ये चर्चा का विषय ही नहीं है कि कौन क्या कर रहा है ? यहां तो बस इस बात में मगन हैं कि हमने क्या कर लिया और आगे क्या करना है ।

निःशुल्क समर कैंप में हो रहा है बच्चों का सर्वांगीण विकास

बैतूल। श्री विनायकम स्कूल द्वारा आयोजित निःशुल्क समर कैंप में विभिन्न रोचक

गतिविधियों द्वारा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास किया जा रहा है। पढ़ाई, खेलकूद एवं को- करिकुलर एक्टिविटीज के अद्भुत मिश्रण से इस निःशुल्क समर कैंप की सार्थक पहचान बन गई है। इस समर कैंप में बच्चों की अभिनय क्षमता एवं रंगमंच से संबंधित कौशल संवर्धन हेतु ड्रामा क्लासेज एवं ओपन माइक वर्कशॉप का संचालन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बच्चों के भीतर छुपी हुई प्रतिभाओं को मंच प्रदान किया जा रहा है। फिजिकल व मेंटल हेल्थ के लिए ध्यान, योग, प्राणायाम और सूर्य नमस्कार से दिन की सकारात्मक शुरुआत की जाती है। साथ ही वॉर्मअप एक्सरसाइज द्वारा शारीरिक फ्लेक्सिबिलिटी और फिटनेस को बूस्टअप किया जाता है। उल्लेखनीय है कि इस निःशुल्क समर कैंप में नर्सरी से लेकर ग्रेड 12 के विद्यार्थियों द्वारा बढ़ चढ़कर भाग लिया जा रहा है, जिसमें आर्ट एंड क्राफ्ट के अंतर्गत पेंसिल वर्क, शेडिंग एवं बेस्ट फॉम द वेस्ट थीम से बच्चों की क्राफ्टिंग स्किल और भी बेहतर हो रही है। जुंबा डांस, वादन व गायन के साथ साथ, विभिन्न आउटडोर गेम्स जैसे क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, आर्चरी और राइफल शूटिंग में बच्चों को खेल की तकनीकी जानकारी दी जा रही है एवं इनडोर गेम्स जैसे टेबल टेनिस, शतरंज और कैरम में नियम और खेल की बारीकियां सिखाई जा रही हैं। इसी के साथ श्री विनायकम स्कूल के इस निःशुल्क समर कैंप में बच्चों की कई स्किल्स पर कार्य किया जाता है, जैसे फायरलेस कुकिंग, जिसमें बच्चों को स्वाद व स्वास्थ्य से भरपूर हेल्दी डिशेस बनाना सिखाया जाता है। यहां केवल सीनियर्स ही नहीं बल्कि नर्सरी से ग्रेड 2 के बच्चे भी अपनी कुकिंग स्किल का अद्भुत परिचय दे रहे हैं। इसके साथ साथ शैक्षणिक उत्कृष्टता एवं संवर्धन हेतु साइंस एवं कॉमर्स की स्पेशल क्लासेज भी संचालित की जा रही है, जिसमें विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के अतिरिक्त विज्ञान और वाणिज्य से जुड़े कई रोचक तथ्यों व विषयों की जानकारी दी जा रही है। यही नहीं व्यक्तित्व विकास के लिए स्पेशल क्लासेस भी बच्चों को प्रदान की जा रही है। जिससे बच्चों की एकेडमिक स्किल का संवर्धन भी किया जा रहा है।

नरवाई जलाने पर किसानों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लेने की मांग, जिला किसान कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन

बैतूल। नरवाई जलाने पर किसानों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को वापस लेने की मांग को लेकर जिला किसान कांग्रेस, बैतूल द्वारा राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष रमेश गायकवाड़ ने कहा कि यह अत्यंत दुख की बात है कि भाजपा सरकार लगातार भोले-भाले किसानों को अपराधी बनाकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा रही है। रमेश गायकवाड़ ने कहा कि वर्तमान भाजपा शासनकाल में किसानों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। एक ओर उन्हें फसलों के वाजिब दाम नहीं मिलते, दूसरी ओर नरवाई

जलाने जैसी मजबूरी को अपराध बताकर उन पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसान आज बच्चों की पढ़ाई, घरेलू खर्च और खेती के साधनों के लिए जमीन तक बेचने को मजबूर हो गया है। उन्होंने बताया कि मजदूरों की अनुपलब्धता के कारण गेहूं की कटाई हारवेस्टर से करनी पड़ती है, जिससे नरवाई खेतों में ही बच जाती है। इस नरवाई को नष्ट करने के लिए सुपर सिडर, रोटावेटर जैसे कृषि यंत्रों की आवश्यकता होती है जो 60 एचपी या उससे अधिक क्षमता के ट्रैक्टरों से चलते हैं, जबकि 90 प्रतिशत किसानों के पास छोटे ट्रैक्टर हैं। ऐसे में बिना नरवाई जलाए बोवनी संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि से अधिक नुकसान उन्हें समर्थन मूल्य न मिलने से हो रहा है। यदि किसानों को सही दाम मिलें तो वे हर प्रकार के आधुनिक कृषि यंत्र खरीद सकते हैं। उन्होंने सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि अनुदान के नाम पर घटिया और बाजार से महंगे उपकरण किसानों को दिए जा रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से किसान कांग्रेस ने मांग की है कि नरवाई जलाने पर किसानों पर दर्ज एफआईआर को तत्काल वापस लिया जाए और सरकार सार्वजनिक रूप से किसानों से माफी मांगे। अन्यथा किसान कांग्रेस किसानों के साथ मिलकर बड़े आंदोलन की तैयारी करेगी। ज्ञापन देने वालों में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष हेमंत वागद्रे, मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के सचिव अक्कू पटेल, सरपंच सोनू धुर्वे, उमराव धोटे, रमेश बरडे, परशराम दवंडे, आनंदराव धोटे, बाबूराव गायकवाड, संजू डेंगे, गजा वामनकर, मुन्नालाल, डागा पवार, गणेश धोटे शामिल थे।

शहर की चौपाटी को महानगरों की तर्ज पर विकसित करने की योजना

नगरीय प्रशासन से कंटेनर फूड शॉप को मंजूरी का इंतजार

संजय द्विवेदी

बैतूल। नगरपालिका ने महानगरों की तर्ज पर शहर की चौपाटी को बनाने की तैयारी है, लेकिन बजट नहीं मिलने से यह योजना फिलहाल ठंडे बस्ते में चली गई है। दरअसल शहर के नेहरू पार्क के पास चौपाटी स्थित है, यहां कई दुकानदार चाट, आईस्क्रीम सहित विभिन्न प्रकार की चटपटी खाद्य चीजों की दुकाने लगाते है। प्रतिदिन यहां सुबह और शाम के समय भारी संख्या में लोग पहुंचते है। इस चौपाटी की रंगत बदलने नगरपालिका ने कंटेनर फूड शॉप का प्रोजेक्ट तैयार किया था, लेकिन अभी तक इसे प्रोजेक्ट को नगरीय प्रशासन से अनुमति नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि नगरीय प्रशासन ने कंटेनर फूड शॉप को नॉन एसओआर आइटम बताते हुए स्वीकृति पर रोक लगा दी है। जिससे पूरा प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में जाता नजर आ रहा है। हालांकि नगरपालिका का कहना है कि विधायक प्रयास करेंगे तो प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल सकती है। बताया गया कि यह प्रोजेक्ट विधायक हेमंत खंडेलवाल द्वारा ही तैयार कराया जा रहा है। जिससे चौपाटी को महानगरों की तर्ज पर विकसित किया जा सके। प्रोजेक्ट की लागत करीब चार से साढ़े चार करोड़ रुपए थी। प्रत्येक कंटेनर फूड शॉप की लागत 2 से 2.50 लाख तक थी।

नॉन एसओआर आइटम बताकर प्रोजेक्ट को किया होल्ड .

नगरपालिका ने चौपाटी के लिए कंटेनर फूड शॉप खरीदने जो प्रोजेक्ट तैयार कर नगरीय प्रशासन को स्वीकृति के लिए भेजा था, उसमें नॉन

एसओआर आइटम बताकर होल्ड किया है। बताया गया कि नॉन एसओआर आइटम का मतलब ऐसे सामान या कार्य जो दरों की अनुसूची (एसओआर) में नहीं दिए गए हों। एसओआर एक सूची होती है जिसमें निर्माण या अन्य परियोजनाओं में आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले सामान और कार्यों की दरें लिखी जाती हैं। यदि कोई सामान या कार्य एसओआर में नहीं दिया गया है, तो उसे नॉन एसओआर आइटम माना जाता है। इसका मतलब है कि उस सामान या कार्य की दर निर्धारित करने के लिए अलग से मूल्यांकन करना होगा, क्योंकि एसओआर में उसकी दर उपलब्ध नहीं है।

120 कंटेनर फूड शॉप बनाने की योजना

महानगरों की तर्ज पर बैतूल में भी चौपाटी को व्यवस्थित बनाने नगरपालिका द्वारा 120 कंटेनर फूड शॉप स्थापित करने की योजना बनाई थी। दरअसल कंटेनर फूड शॉप एक प्रकार का रेस्टोरेंट या फूड वेंडिंग का बिजनेस मॉडल है जो परिवहन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कंटेनरों को बदलकर फूड शॉप में तब्दील कर देता है।

ये शॉप आमतौर पर टिकाऊ, पोर्टेबल और लागत- प्रभावी होते हैं। इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है, जिससे उन्हें विभिन्न लोकेशन पर संचालित करने की सुविधा मिलती है। ये पारंपरिक दुकानों की तुलना में बनाने और स्थापित करने में कम खर्च करते हैं। इन्हें डिजाइनों और आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है।

नगरपालिका ने नहीं छोड़ी उम्मीद, प्रयास जारी

नगरीय प्रशासन ने कंटेनर फूड शॉप को नॉन एसओआर आइटम बताते हुए इस प्रोजेक्ट को भले ही होल्ड कर दिया हो, लेकिन नगरपालिका ने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है।

बताया जा रहा है कि बैतूल विधायक ने खुद इस प्रोजेक्ट के लिए नगरपालिका को निर्देशित किया था। जिसके बाद नगरपालिका ने चौपाटी के लिए प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार कर टीएस के लिए नगरीय प्रशासन को भेजी गई थी, लेकिन नॉन एसओआर आइटम बताकर इसे होल्ड कर दिया है। इस संबंध में नपा सीएमओ को कहना है कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। प्रयास किये जायेगे कि जल्द ही प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल जाए।

इनका कहना है -

चौपाटी पर कंटेनर फूड शॉप बनाने की योजना है। लेकिन अभी नगरीय प्रशासन से इसे मंजूरी नहीं मिली है। हमारा प्रयास जारी है। जैसे ही मंजूरी मिलती है, इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर देगे।

- सतीश मटसेनिया, सीएमओ, नगरपालिका बैतूल

प्रकरण लंबित रखने पर संबंधित अधिकारी पर लगेगा 500 रुपए का जुर्माना : कलेक्टर

समयावधि प्रकरण में 5 हजार रुपए तक जुर्माना होगा अधिरोपित

बैतूल। समयावधि के प्रकरण अनावश्यक लंबित पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही ऐसे प्रकरण जो लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत चिन्हित सेवा से संबंधित है उनमें 5 हजार रुपए तक जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा। यह निर्देश बैतूल कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने सभी अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि कलेक्टर कार्यालय से जुड़े समयावधि प्रकरण में संबंधित डिप्टी कलेक्टर और जिला पंचायत के प्रकरण में संबंधित परियोजना अधिकारी पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। बैठक में कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने विभागवार सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सख्त निर्देशित किया कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जनजातीय कार्य, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जलसंसाधन, सामाजिक न्याय इत्यादि विभाग शिकायतों के निराकरण में विशेष ध्यान दे।

उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को उनकी विभागीय योजनाओं में शत प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र शासन की योजनाओं के लाभ से वंचित न रहें। जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा कर कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने सभी जनपद सीईओ को अमृत सरोवर, खेत तालाब, सोखता पीट, कूप रिचार्ज इत्यादि जल संरचना के निर्माण में शत प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को भी एफआरए प्लांट, ग्रीन हार्वेस्टिंग, पानी के अपव्यय को रोकने इत्यादि जल संरचनाओं के निर्माण शीघ्र करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सतत मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम गठित किया जाए। उन्होंने शिक्षा विभाग को स्कूलों में रंगोली, पोस्टर, निबंध, इत्यादि जागरूकता की गतिविधियां सतत आयोजित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने बैठक में सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि अभियान चलाकर अपने क्षेत्र में समग्र ईकेवाईसी के शेष लक्ष्य को पूर्ण कराएं। उन्होंने सभी जनपद सीईओ, सीएमओ को भी अभियान के तहत निर्धारित लक्ष्य को आगामी शनिवार तक पूर्ण करने के निर्देश दिए

आबकारी अधिकारी का वेतन रोकने के निर्देश- कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने बैठक में विभागवार ई ऑफिस प्रणाली के क्रियान्वयन की भी समीक्षा कर सभी विभागों को ई ऑफिस का प्रभावी क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। उन्होंने आबकारी विभाग को ई ऑफिस चालू नहीं करने पर जिला आबकारी अधिकारी का वेतन रोकने के निर्देश दिए। सड़क दुर्घटना के ज्ञात और अज्ञात प्रकरणों की समीक्षा कर कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने सभी एसडीएम को सभी प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए संवेदनशील सड़कों पर सुरक्षा के सभी आवश्यक उपाय किए जाएं। सड़क दुर्घटना में घायलों को त्वरित स्वास्थ्य लाभ मिले।

बैतूल में लोक सेवा गारंटी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नई पहल

बैतूल। जनता को शासकीय सेवाओं का लाभ समय पर और पारदर्शी रूप से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने एक अभिनव पहल की शुरुआत की है। इस नवाचार के अंतर्गत लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्राप्त आवेदनों पर प्रत्येक विभाग को प्रतिदिन कम से कम तीन नागरिकों से संवाद कर उनके निराकरण प्रगति की जानकारी लेना अनिवार्य किया गया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नागरिकों को उनकी निर्धारित सेवाएं समयसीमा में प्राप्त हुईं या नहीं। यदि किसी सेवा में देरी या समस्या पाई जाती है, तो संबंधित विभाग त्वरित और उचित कार्यवाही करेगा। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने इस नवाचार की प्रभावी निगरानी के लिए एक निर्धारित फॉर्मेट तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। यह फॉर्मेट सभी विभागों द्वारा भरकर नियमित रूप से प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे इसकी सतत मॉनिटरिंग संभव होगी। यह पहल न केवल शासन की जवाबदेही को मजबूत करेगी, बल्कि आम जनता में विश्वास भी बढ़ाएगी कि प्रशासन उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेकर समाधान के लिए तत्पर है।

कलेक्टर और एडीएम भी करेंगे प्रतिदिन संवाद : नवाचार की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए कलेक्टर श्री सूर्यवंशी स्वयं एवं एडीएम स्तर के अधिकारी भी प्रतिदिन तीन नागरिकों से संवाद कर फीडबैक प्राप्त करेंगे।

ई-उपार्जन पोर्टल पर तुअर फसल पंजीयन की अवधि 15 मई तक बढ़ाई गई

बैतूल। भारत सरकार की प्राईस सपोर्ट स्कीम अन्तर्गत ई-उपार्जन पोर्टल पर 25 मार्च से 30 अप्रैल 2025 तक जिले में तुअर फसल का पंजीयन के लिए नियत की गई थी। किन्तु अब कृषक हित को ध्यान में रखकर शासन द्वारा पंजीयन की अंतिम तिथि 15 मई 2025 नियत की गई है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उप संचालक ने बताया कि किसान भाई, जिन्होंने तुअर फसल की बुवाई की हो पंजीयन की कार्यवाही कार्यालयीन समयानुसार (शासकीय अवकाश दिवसों को छोडक़र) पंजीयन के लिए निर्धारित लिंक में जाकर स्वयं के मोबाईल, कम्प्यूटर तथा ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालय के सुविधा केन्द्रों और सहकारी विपणन समिति द्वारा संचालित केन्द्रों अथवा एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेन्टर कियोस्क, लोक सेवा केन्द्रों, साइबर कैफे पर पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज (भू-स्वामियों के लिये भूमि संबंधी दस्तावेज, आधार कार्ड, आधार नम्बर से पंजीकृत मोबाईल नम्बर एवं अन्य फोटो पहचान पत्र तथा सिकमी एवं वन पट्टाधारी किसान वनाधिकारी पट्टाधारी, सिकमीदार को आधार कार्ड, आधार नम्बर से पंजीकृत मोबाईल नम्बर एवं वनपट्टा एवं सिकगी अनुबंध की प्रति) के माध्यम से करवा सकते हैं। उप संचालक कृषि कहा कि किसान भाई ध्यान देवें कि उनसे उपार्जित फसल का भुगतान उनके आधार नम्बर से लिंक बैंक खाते में सीधे किया जावेगा। किसान भाई अपने आधार नम्बर से बैंक खाता तथा मोबाईल नम्बर लिंक कराकर उसे अपडेट रखें ताकि भविष्य में असुविधा न हो।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में प्रभात पट्टन के 269 पात्र जोड़े विवाह के अटूट बंधन में बंधे

विधायक के मुख्य आतिथ्य में धूमधाम से संपन्न हुआ सामूहिक विवाह कार्यक्रम

बैतूल। मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के तहत मुलताई के प्रभात पटट्न में सोमवार को आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में पात्र 269 जोड़े विवाह के अटूट बंधन में बंधे। कार्यक्रम में गोंडी बैंड बाजे एवं डीजे के साथ धूमधाम से बारात बजरंग बली मंदिर से निकाली, जो कार्यक्रम स्थल पर पहुंची जहां बारात का भव्य स्वागत स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने किया। कार्यक्रम में 63 जोड़ों का वैदिक रीति रिवाज, 156 जोड़ो का भूमका रीति और 1 निकाह, एवं बौद्ध धर्म से 49 जोड़ो का विवाह संपन्न हुआ। भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा वर वधु और उनके साथी परिजनों के लिए बैठक सहित पेयजल, भोजन, कूलर इत्यादि की उत्तम व्यवस्था की गई। कार्यक्रम में सभी नव दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर रहे 269 जोड़ो को 49 हजार की राशि भी अंतरित की गई। विवाह सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासन द्वारा 269 जोड़ो के लिए कुल 07 सैक्टर बनाएं गए। लगभग 28 वेदियां बनाई गई। प्रत्येक वेदी पर चार जोड़ो का विवाह कराया गया। सैक्टर पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के लिए सैक्टर प्रभारी और सहायक सैक्टर प्रभारी बनाएं गए। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में जनपद, राजस्व, सामाजिक

न्याय, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग के अमले ने सक्रिय भूमिका निभाई। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फायर ब्रिगेड एंबुलेंस और मेडिकल टीम भी मौके पर तैनात रही। इस अवसर पर सोनाली विनोद पटेल, अनुविभागीय अधिकारी मुलताई अनिता पटेल, उप संचालक सामाजिक न्याय रोशनी वर्मा, जनपद सीईओ और अन्य अधिकारियों ने कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाई।

विधायक मुलताई चन्द्रशेखर देशमुख ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मध्यप्रदेश सरकार की अंतरात्मा से निकली एक महत्वपूर्ण योजना है। निर्धन परिवार जो अपनी बेटियों के विवाह को लेकर चिंतित रहते थे, उनकी चिंता को इस योजना ने जड़ से समाप्त किया हैं। योजना के तहत धूमधाम से विधिवत विवाह सम्पन्न कराने के साथ ही 49 हजार की राशि भी वर और वधु को दी जा रही हैं, जो उनके नव वैवाहिक जीवन के शुरुआत का आधार बनेगी। उन्होंने सभी जोड़ो को मंगल शुभकामनाएं दी। विधायक श्री देशमुख ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव की मंशानुरूप प्रदेश के साथ बैतूल जिले में भी व्यापक स्तर पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। निर्धन परिवार जो अपनी जमीन, जायदाद को बेचकर अपनी बेटियों का विवाह कराते थे, उनके लिए यह योजना वरदान साबित हुई हैं। कार्यक्रम में सुधाकर पवार ने भी संबोधित करते हुए सभी वर वधु को शुभकामनाएं दी।

सावलमेंढा के सामूहिक विवाह सम्मेलन में 739 जोड़े ने लिए सात फेरे

बैतूल। भैंसदेही के सावलमेंढा में 5 मई को आयोजित हुए सामूहिक विवाह सम्मेलन में 739 जोड़ों ने सात फेरे लेकर जीवन भर साथ निभाने का संकल्प लिया। इस आयोजन में कुल 745 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें 6 मुस्लिम जोड़ों ने अपने धार्मिक रीति-रिवाजों से निकाह किया। हर धर्म के जोड़ों की शादी उनकी परंपराओं के अनुसार कराई गई, जिससे यह सम्मेलन सामाजिक समरसता और धार्मिक सौहार्द की मिसाल बन गया। कार्यक्रम में भैंसदेही विधानसभा क्षेत्र के विधायक महेंद्र सिंह चौहान, सुधाकर पवार, राजा ठाकुर, जनपद पंचायत अध्यक्ष, नगर परिषद अध्यक्ष सहित अनेक जनप्रतिनिधि, एसडीएम शैलेंद्र हनोतिया, जनपद सीईओ देवेंद्र दीक्षित उपस्थित रहे। प्रशासनिक अधिकारियों ने दूल्हा-दुल्हन की बैठने की व्यवस्था से लेकर भोजन, मंच और विवाह मंडपों तक हर पहलू पर बारीकी से निगरानी रखी गई। यह सामूहिक विवाह सम्मेलन आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए संबल बना, समाज में एक सकारात्मक संदेश भी गया कि सभी धर्म, जाति और वर्ग के लोग एक मंच पर आकर सामाजिक परंपराओं को मजबूती दे सकते हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत पात्र कन्याओं को उनके विवाह के समय कुल 55 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें 49 हजार रुपये का चेक सीधे कन्या के नाम से दिया जाता है ताकि वह अपने नए जीवन की शुरुआत सशक्त रूप से कर सके, जबकि 6 हजार रुपये विवाह समारोह के आयोजन के लिए दिए जाते हैं। इस योजना का लाभ वही परिवार उठा सकते हैं जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों, जिनकी कन्या की उम्र कम से कम 18 वर्ष और वर की उम्र 21 वर्ष हो। योजना का बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना है, जिसका क्रियान्वयन सामाजिक न्याय एवं नि-शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है।

बस स्टैंड से लल्ली चौक तक सड़क निर्माण में बिजली कंपनी और नगरपालिका में फिर हुई खींचतान

एक सप्ताह से अटका मामला, ठेकेदार ने रोका निर्माण, वैवाहिक सीजन में व्यापारियों की फजीहत

बैतूल। कोठीबाजार क्षेत्र में बस स्टैंड से लल्ली चौक तक बनाई जा रही टू-लेन सडक़ के निर्माण में देरी को लेकर जहां उस क्षेत्र के व्यापारियों में रोष है, वहीं निर्माण में देरी को लेकर नगरपालिका और बिजली कंपनी द्वारा एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोडा जा रहा हैं। टू-लेन सडक़ निर्माण कार्य को शुरू हुए अभी कुछ एक दिन ही हुए थे कि अचानक से कार्य पुन- रूक गया। सडक़ की एक लेन जहां महज चार दिनों के भीतर ही पूर्ण कर ली गई, वहीं दूसरी लेन का कार्य एक सप्ताह से भी अधिक समय से बंद पड़ा है। नगरपालिका के कर्मचारियों द्वारा बताया जा रहा है कि बिजली कंपनी द्वारा परमिट जारी न होने के कारण यहां देरी हो रहीं है। निर्माण कार्य कर रही कंपनी के अनुसार सडक़ के जिस हिस्से में निर्माण कार्य किया जाना है, वहां पुराने ट्रांसफार्मर सहित बिजली के पोल बाधा बन रहे हैं। नपा ने इस बारे में बिजली विभाग को सूचित कर दिया था, लेकिन बिजली विभाग द्वारा न तो परमिट जारी किया जा रहा है और न ही ट्रांसफार्मर एवं पोल शिफ्टींग का कार्य का सुपर विजन किया जा रहा है।

जिसके परिणाम स्वरूप ठेकेदार को मजबूरी में कार्य रोकना पड़ा है। नगरपालिका के विद्युत शाखा प्रभारी अमित सक्सेना ने हरीभूमि को बताया कि सोमवार दोपहर को हमारे द्वारा विद्युत सप्लाई के चालू रहते ही सडक़ के किनारे के पेड़ों की छटिंग कराई गई। यह बड़ा हाई रिस्क का काम था, परंतु बिजली कंपनी के द्वारा परमिट नहीं मिलने की वजह से ऐसा करना हमारी मजबूरी थी। बिजली कंपनी के सब इंजीनियर को सूचित करने के बावजूद परमिट में विलंब किया जा रहा था। काफी देर बाद में बिजली विभाग के कार्यपालन अभियंता श्री बघेल द्वारा स्वयं स्पॉट पर आकर निरीक्षण किया गया एवं बिजली बंद करवाई गई। इस क्षेत्र के व्यापारियों का कहना है कि यहां सडक़ खुदी पड़ी है। इससे आए दिन धूल के अलावा ट्रैफिक जाम की समस्या हो रही है। यदि निर्माण कार्य जल्द पूरा नहीं हुआ तो समस्या बढ़ जाएगी। वैवाहिक सीजन का समय होने से ग्राहकी करने में परेशानी अलग हो रही है, जिससे हमे आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। सोमवार को व्यापारियों ने पेड़ काटने के दौरान नगर पालिका के कर्मचारियों से पेड़ को न काटकर सिर्फ पेड़ की छटिंग करने का आग्रह किया, वहीं निर्माण के चलते दोनों तरफ से सडक़ बंद कर दी गई है। इधर सडक़ बंद होने से कोठीबाजार से गंज, सदर आने-जाने वाले मार्ग पर ट्रैफिक का भारी दबाव हो गया है।

इनका कहना है -

हमारे द्वारा सडक़ का निर्माण जल्द से जल्द पूरा करवाने की कोशिश की जा रही है परंतु बिजली कंपनी से समय पर परमिट नहीं मिलने की वजह से काम में अनावश्यक विलंब हो रहा है। आज सोमवार को बिजली कंपनी द्वारा परमिट न देने पर हमारे द्वारा विद्युत सप्लाई के चालू रहते ही सडक़ के किनारे के पेड़ काटे गए। जो बड़ा हाई रिस्क का काम था। काफी देर बाद बिजली कंपनी के बघेल सर ने आकर विद्युत सप्लाई बंद कराई। उनके द्वारा कल से परमिट में विलंब न होने का आश्वासन भी दिया है।

अमित सक्सेना, विद्युत शाखा प्रभारी, नपा बैतूल

मेंटेनेंस के कारण आज बंद रहेगी बिजली

बैतूल। बिजली कंपनी द्वारा आज 6 मई को 11 केव्ही टाउन-2 फीडर का मेंटेनेंस कार्य किया जाना है। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बैतूल जोन-2 शहर प्रबंधक ने बताया कि मेंटेनेंस कार्य के चलते मंगलवार को प्रात- 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक कोठी बाजार, कंपनी गार्डन, आजाद वार्ड, बस स्टैंड, एमजी कॉम्पलेक्स, लल्ली चौक, सीमेंट रोड, जिला जेल, गांधी चौक, नगर पालिका परिसर, बारस्कर कॉलोनी, मछली बाजार आदि क्षेत्र में विद्युत सप्लाई बंद रहेगी।

प्रदेश में ओला-उबर जैसी सरकारी टैक्सी चलेगी

कैब मालिकों-ड्राइवरों को मिलेगा ज्यादा मुनाफा; कमीशन का झंझट भी नहीं होगा

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश के बड़े शहरों में अब ओला-उबर की तर्ज पर सरकारी कैब 'सहकार टैक्सी' दौड़ती नजर आएगी। इसके संचालन के लिए सहकारिता विभाग तैयारियों में जुटा है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने संसद के पिछले सत्र में 'सहकार टैक्सी' शुरू करने की घोषणा की थी। इसके बाद से मध्यप्रदेश के सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग इस सेवा को शुरू करने की तैयारियों में सक्रिय हैं।

सरकार, प्राइवेट कैब सेवाओं की तरह 'सहकार टैक्सी' के लिए एक एप बनाने पर विचार कर रही है। सरकारी कैब सर्विस में टैक्सी संचालन करने वाले वाहन मालिक और ड्राइवर को हर ट्रिप का पूरा पैसा मिलेगा। वर्तमान में ओला और उबर जैसी निजी कैब कंपनियां 20 से 40 प्रतिशत तक कमीशन लेती हैं। लेकिन सहकार टैक्सी में मामूली पोर्टल शुल्क और टैक्स को छोड़कर पूरा पैसा सीधे कैब संचालक को मिलेगा।

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने संसद में किया था ऐलान

संसद में 26 मार्च 2025 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा था कि आने वाले दिनों में ओला-उबर जैसी एक बहुत बड़ी को-ऑपरेटिव सहकारी टैक्सी सर्विस आने वाली है। उसका मुनाफा धन्नासेठों के हाथ में नहीं जाएगा। वो ड्राइवर के पास जाएगा।

मप्र कांग्रेस ने खत्म किया मुख्य प्रवक्ता का पद

संगठन प्रभारी ने की 53 प्रवक्ताओं की नियुक्ति, 4 पूर्व विधायक लिस्ट से बाहर

भोपाल (नप्र)। एमपी कांग्रेस के मीडिया विभाग में बदलाव किया गया है। पिछले साल 27 मार्च को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मीडिया विभाग के अध्यक्ष केके मिश्रा की जगह मुकेश नायक को अध्यक्ष नियुक्त किया था। साथ ही 9 मुख्य प्रवक्ता और 22 प्रवक्ताओं की नियुक्ति की थी। कांग्रेस ने अब मुख्य प्रवक्ता का पद खत्म कर दिया है। कांग्रेस के संगठन प्रभारी संजय कामले ने अब 53 प्रवक्ताओं की नियुक्ति की है।

करूणाधाम में रक्तदान शिविर 6 को

भोपाल। करुणाधाम मातृशक्ति ब्रह्मलीन मातुश्री स्मृति दिवस पर रक्तदान शिविर मंगलवार 6 मई को शाम 5 बजे से होगा। करुणाधाम आश्रम में ब्रह्मलीन मातुश्री श्रीमती दुर्गा शाण्डिल्य की स्मृति में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आश्रम के श्री शाश्वत शाण्डिल्य ने बताया कि पीठाधीश्वर गुरूदेव श्री सुदेश शाण्डिल्य महाराज के मार्गदर्शन में बड़ी संख्या में शिविर में युवा रक्तदान करेंगे। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है। रक्तदान से हम सब मिलकर किसी जरूरतमंद का जीवन बचा सकते हैं।

गुरूदेव की जयंती पर 'प्रणति पर्व' में 7 को, गूँजेगा रवीन्द्र संगीत

भोपाल। गुरूदेव रबीन्द्रनाथ टैगोर की जयंती पर 'प्रणति पर्व' का आयोजन टैगोर विश्व कला एवं संस्कृति केन्द्र द्वारा 7 मई को किया जा रहा है। इस अवसर पर रवीन्द्र संगीत के वृन्दगान की प्रस्तुति आकर्षण का केन्द्र होगी। इस प्रस्तुति का निर्देशन रंगकर्मी रीना सिन्हा और संगीतकार मॉरिस लॉज़रस करेंगे। इस गायन समूह में रेनीवृन्द के कलाकार हिस्सा लेंगे।

टैगोर कला केन्द्र के निदेशक विनय उपाध्याय ने बताया कि 'प्रणति पर्व' में गुरूदेव टैगोर के गीतों पर आधारित दृश्य-श्रव्य रूपक 'गीतांजलि' पर केन्द्रित बहुरंगी पुस्तिका का लोकार्पण भी किया जाएगा। समारोह का आरंभ रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्व विद्यालय में स्थापित टैगोर प्रतिमा पर सामूहिक पुष्पांजलि से होगा। उसके उपरांत 'मुक्तधारा' सभागार में सांस्कृतिक प्रस्तुति होगी। आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम प्रभारी राजेश भट्ट समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। प्रति कुलाधिपति डॉ. अदिति चतुर्वेदी वत्स, कुलगुरू डॉ. आर.पी. दुबे और कुलसचिव डॉ. संगीता जौहरी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। समारोह का आयोजन विश्वरंग फाउंडेशन और टैगोर राष्ट्रीय नाट्य, विद्यालय के सहयोग से किया जा रहा है।

मीडिया सलाहकार ताहिर अली को वैवाहिक वर्षगाँठ पर दी शुभकामनाएँ

भोपाल। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने अपने मीडिया सलाहकार श्री ताहिर अली को उनकी विवाह की 40वीं वर्षगाँठ के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएँ दीं। उप

मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने श्री ताहिर अली को मंत्रालय भोपाल में पुष्पगुच्छ भेंट कर सुखद, स्वस्थ एवं समृद्ध दांपत्य जीवन की कामना की। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने श्री ताहिर अली और उनकी धर्मपत्नी को इस पावन अवसर पर हार्दिक बधाई दी और प्रेम, विश्वास और सौहार्द से परिपूर्ण जीवन व्यतीत करने की कामना की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल के विशेष सहायक श्री चन्द्रप्रताप गोहल, निज सचिव श्री आनंद भट्ट, ओएसडी श्री अशोक शर्मा और जनसंपर्क अधिकारी श्री अंकुश मिश्रा उपस्थित थे। सभी ने श्री ताहिर अली को पुष्पगुच्छ प्रदान कर हार्दिक शुभकामनाएँ दीं।

उल्लेखनीय है कि श्री ताहिर अली विगत 21 वर्षों से उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल के साथ मीडिया समन्वय एवं जनसंपर्क गतिविधियों का सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं। उनके कुशल नेतृत्व, लेखन क्षमता एवं मीडिया के प्रति सजग दृष्टिकोण ने उन्हें एक प्रतिष्ठित और विश्वसनीय सलाहकार के रूप में स्थापित किया है। उप मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी श्री अली को शुभकामनाएँ प्रेषित करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

मुख्यमंत्री ने किये भगवान विष्णु वराह के दर्शन

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जबलपुर के मझौली में भगवान विष्णु वराह के दर्शन करविष्णु वराह मंदिर में पूजा अर्चना की तथा प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की। संस्कृति, पर्यटन एवं धार्मिक न्यास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी, सांसद श्री आशीष दुबे, विधायक श्री अजय विश्नोई, श्री राजकुमार पटेल भी इस अवसर पर उनके साथ थे।जबलपुर से लगभग 45 किलोमीटर दूर मझौली स्थित विष्णु वराह मंदिर का निर्माण 11 वीं सदी में किया गया था। कालांतर में ध्वस्त हुये कल्चुरीकालीन इस मंदिर का 18 वीं शती में पुनर्निर्माण कराया गया। बताया जाता है कि इस मंदिर में स्थापित भगवान विष्णु वराह की प्रतिमा विश्व की सबसे बड़ी और एकमात्र ऐसी प्रतिमा है जिसकी पूजा होती है। इसे 11वीं सदी में मंदिर के गर्भ गृह में स्थापित किया गया था। धार्मिक एवं पौराणिक महत्व का विष्णु वराह मंदिर कला की दृष्टि से भी उत्कृष्ट है और राज्य सरंक्षित स्मारकों में शामिल है।

जन्मजात फेफड़ों की विकृति से पीड़ित नवजात की सफल सर्जरी

3 सप्ताह के वेंटिलेटर सपोर्ट के बाद मिली नई ज़िंदगी

भोपाल। एम्स भोपाल ने कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के मार्गदर्शन में एक महत्वपूर्ण चिकित्सकीय उपलब्धि हासिल करते हुए जन्मजात डायाफ्रामिक हर्निया नामक गंभीर जन्मजात विकृति से पीड़ित एक कम वज़न वाले नवजात शिशु की सफलतापूर्वक सर्जरी कर उसे नया जीवन प्रदान किया गया है। यह मामला जन्म से पूर्व ही, गर्भावस्था के सातवें माह में, जटिल स्थिति के रूप में चिन्हित हो गया था। विशेषज्ञों की सलाह के पश्चात परिजनों ने एम्स भोपाल के लेबर रूम में प्रसव कराने का निर्णय लिया, जहाँ शिशु का सुरक्षित जन्म हुआ। जन्म के समय उसका वज़न केवल 2.2 किलोग्राम था, और जन्मजात विकृति के कारण उसे सांस लेने में अत्यधिक कठिनाई हो रही थी। शिशु को तुरंत वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया और लगभग तीन सप्ताह तक उसकी गहन निगरानी की गई। इसके उपरांत, एम्स भोपाल की बाल शल्य चिकित्सा टीम द्वारा अत्यंत जटिल ऑपरेशन सफलता पूर्वक संपन्न किया गया। सभी

चिकित्सकीय चुनौतियों को पार करते हुए शिशु ने स्वस्थ रूप से रिकवरी की है और अब उसका वज़न बढ़कर लगभग 2.9 किलोग्राम हो गया है। परिजनों ने एम्स भोपाल में नवजात शिशुओं के लिए की जा रही जटिल शल्य चिकित्सा सेवाओं की सराहना करते हुए, निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण इलाज के लिए संस्थान का आभार प्रकट किया।

इस अवसर पर प्रो. (डॉ.) अजय सिंह ने कहा यह उदाहरण दर्शाता है कि एम्स भोपाल में अत्याधुनिक नवजात चिकित्सा और शल्य चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो जटिल जन्मजात स्थितियों में भी जीवन रक्षक सिद्ध हो रही हैं। हमें गर्व है कि हम मध्यप्रदेश एवं आसपास के क्षेत्रों में उन्नत बाल स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं।

बालिका से बैड टच के आरोपी को सजा

भोपाल। भोपाल में कुमुदिनी पटेल विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हेयर कटिंग के दौरान पांच साल की मासूम के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी मोहम्मद जैद पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। इस केस में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिव्या शुक्ला और ज्योति कुजूर ने पैरवी की थी। जानकारी के मुताबिक 26 जून 2022 को पीड़िता की मां ने पुलिस थाना अशोका गार्डन शिकायत दर्ज कराई की मोहम्मद जैद अस्सी फीट रोड पर हेयर कटिंग की शॉप का संचालन करता है।बच्ची के बाल कटवाने के लिए उसके पास पहुंचे थे। आरोपी ने हेयर कटिंग के दौरान बच्ची के साथ बैड टच किया। इस बात की जानकारी मासूम ने घर पहुंचने के बाद दी।शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। तीन साल बाद केस का ट्रायल चलने के बाद सोमवार को आरोपी को सजा सुनाई गई है।

ट्रिपलआईटीडीएम के गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियों के न्यूड वीडियो बनाकर दोस्त को भेजती थी छात्रा...

बाथरूम में नहा रही सीनियर ने पकड़ा,कॉलेज के छात्र-छात्राएं थाने पहुंचे, प्रबंधन ने जब्त किया मोबाइल

जबलपुर (नप्र)। जबलपुर के ट्रिपलआईटीडीएम के गर्ल्स हॉस्टल में एक छात्रा द्वारा दूसरी लड़कियों के न्यूड वीडियो बनाकर अपने दोस्त को भेजने सनसनीखेज मामला सामने आया है। वो दो साल से ऐसा कर रही थी। बाथरूम में नहा रही एक सीनियर छात्रा ने उसे अपना वीडियो बनाते हुए पकड़ लिया, जिसके बाद इसका खुलासा हुआ। जिस दोस्त को वह वीडियो भेजती थी वो दिल्ली में रहता था।

ट्रिपल आईटीडीएम जबलपुर में छात्रा का अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। छात्रा बीटेक चतुर्थ वर्ष की बताई जा रही है, जिसका अश्लील वीडियो बनाया जा रहा था। छात्रा बाथरूम में नहाते वक्त यह वीडियो बनाया जा रहा था। वीडियो जूनियर छात्रा द्वारा बनाने की बात सामने आई है। पूरी घटना संस्थान के सरस्वती छात्रावास की बताई जा रही है।

इस मामले में ट्रिपल आईटीडीएम के छात्र थाने में शिकायत करने पहुंचे है। पूरे मामले में डायरेक्टर डॉ. बीके सिंह ने कहा कि उन्हें गत दिवस इस मामले की जानकारी मिली थी।

छात्रा वाशरूम में एक अन्य छात्रा का वीडियो बना रही थी। उसके फोन और लैपटाप जब्त कर लिया गया है, आरोपित छात्रा को गेस्ट हाउस में सुरक्षित पूछताछ के लिए रखा गया है। छात्रा स्वजनों को भी जानकारी दी गई है।

अश्लील वीडियो के रैकेट से जुड़े होने की आशंका

छात्रा के अश्लील वीडियो बनाने वाले रैकेट से जुड़े होने की आंशका है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अब उस दोस्त भी जानकारी निकाली जा रही है, जिसे यह छात्रा लड़कियों के वीडियो भेजा करती थी।

एम्स भोपाल और पतंजलि अनुसंधान संस्थान के बीच एकीकृत चिकित्सा और शोध सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण संवाद

भोपाल। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह ने हरिद्वार स्थित पतंजलि योगपीठ का दौरा किया और वहाँ स्वामी रामदेव जी तथा आचार्य बालकृष्ण जी से भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने पतंजलि अनुसंधान संस्थान के अत्याधुनिक अनुसंधान प्रयोगशाला एवं एनिमल हाउस का भी निरीक्षण किया। दौरे के दौरान एम्स भोपाल एवं पतंजलि अनुसंधान संस्थान के बीच भावी शोध सहयोग की संभावनाओं पर गंभीर विचार-विमर्श हुआ। प्रो. सिंह ने स्वामी रामदेव जी को एम्स भोपाल में एकीकृत चिकित्सा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों

की जानकारी दी। साथ ही, उन्होंने नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) के माध्यम से नई शिक्षा नीति के अंतर्गत एमबीबीएस पाठ्यक्रम में आयुष विषयों के समावेशन पर भी विचार साझा किया। इस अवसर पर आचार्य बालकृष्ण जी ने यह बताते हुए प्रसन्नता व्यक्त की कि उन्होंने एम्स भोपाल द्वारा जनजातीय स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों के बारे में सुना है। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि एम्स भोपाल की ओर से कोई प्रभावशाली शोध परियोजना प्रस्तावित की जाती है, तो पतंजलि अनुसंधान संस्थान न केवल उसके वित्तपोषण पर विचार करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर शोधार्थियों को भी सहयोग प्रदान किया जाएगा।

इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, प्रो. (डॉ.) अजय सिंह ने कहा, स्वामी रामदेव जी एवं आचार्य बालकृष्ण जी से भेंट और संवाद अत्यंत सार्थक रहा। एम्स भोपाल देश में आधुनिक चिकित्सा को पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के साथ एकीकृत करने के लिए प्रतिबद्ध है। पतंजलि जैसे संस्थान के साथ मिलकर काम करने से अनुसंधान को नई दिशा मिलेगी और यह स्वास्थ्य प्रणाली को अधिक समग्र एवं सुलभ बनाने में मदद करेगा।

एम्स भोपाल का फिज़ियोलॉजी विभाग करेगा राष्ट्रीय क्विज़ का आयोजन

भोपाल। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के मार्गदर्शन में फिज़ियोलॉजी विभाग द्वारा नेशनल अंडरग्रेजुएट फिज़ियोलॉजी क्विज़-छठा संस्करण का आयोजन 19, 20 एवं 30 मई 2025 को किया जा रहा है। इस प्रतिष्ठित शैक्षणिक आयोजन में देशभर के विभिन्न मेडिकल संस्थानों से छात्र-छात्राएं भाग लेंगे। एम्स भोपाल के फिज़ियोलॉजी विभाग ने पूर्व में इसके पाँच संस्करणों का सफल आयोजन कर चिकित्सा छात्रों में ज्ञान, तर्कशीलता एवं अकादमिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने का कार्य किया है। इस वर्ष का आयोजन दो चरणों में संपन्न होगा। स्क्रीनिंग राउंड 19 एवं 20 मई 2025 को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया जाएगा, जबकि मुख्य कार्यक्रम 30 मई 2025 को एम्स भोपाल में आयोजित किया जाएगा।

प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रत्येक टीम में 2 छात्र होंगे, और प्रत्येक कॉलेज से अधिकतम 2 टीमें भाग ले सकेंगी। पहले 100 पंजीकरण प्राप्त करने वाली टीमें ही प्रतियोगिता में सम्मिलित हो पाएंगी। सभी प्रतिभागियों को ई-सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएंगे और विजेता टीमों को पुरस्कृत किए जाएंगे।

भोपाल मंडल में लूप लाइन संरक्षा को लेकर प्रभावी प्रयास, यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि

भोपाल। रेल यात्रियों की संरक्षा और निर्बाध परिचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पश्चिम मध्य रेलवे, भोपाल मंडल द्वारा स्टेशन यार्डों और लूप लाइनों के उन्नयन एवं निरीक्षण कार्यों को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। रेलवे यार्ड न केवल गाड़ियों के ठहराव और पारगमन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, बल्कि मालगाड़ियों और बिना ठहराव वाली तेज गति की ट्रेनों के संचालन की दृष्टि से भी इनका बड़ा योगदान होता है।

भोपाल मंडल में कुल 2224 किलोमीटर ट्रैक परिचालन हेतु उपलब्ध है, जिसमें 88 स्टेशन यार्ड सम्मिलित हैं। इन यार्डों में मेन लाइन के अतिरिक्त लूप लाइनें होती हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य ट्रेनों के सुगम संचालन को सुनिश्चित करना है। एक लूप लाइन की औसतन लंबाई लगभग 700 मीटर होती है, और यह मेन लाइन या अन्य लूप लाइन से टर्नआउट के माध्यम से जुड़ी रहती है।

मंडल के यार्डों में 204 पैसेंजर रनिंग लाइनें और 256 नॉन-पैसेंजर रनिंग लाइनें कार्यरत हैं। इन लाइनों पर संरक्षा सुनिश्चित करने हेतु नियमित रूप से ट्रैक पैरामीटर की तीन माह और छह माह की आवृत्तियों पर जांच की जा रही है। निरीक्षण के दौरान पाए गए दोषों को त्वरित गति से ठीक करने की प्रक्रिया भी पूरी पारदर्शिता के साथ अपनाई जा रही है।

संरक्षा के इसी क्रम में मंडल ने यार्ड संरचना को आधुनिक बनाने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। वर्तमान में 83 यार्डों में से 35 यार्डों का उन्नयन कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जबकि शेष यार्डों पर कार्य प्रगति पर है। उन्नयन कार्यों में फ्री रेल जॉइंट्स को हटाना, पुराने टर्नआउट को प्रतिस्थापित करना, गिट्टी की छनाई, ड्रेनेज सुधार और ट्रैक फिटिंग्स का प्रतिस्थापन जैसे कार्य प्रमुख रूप से सम्मिलित हैं।

भोपाल मंडल ने वर्ष 2024-25 में यार्डों की सुरक्षा और कार्यकुशलता को बढ़ाने हेतु लगभग 244 करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। इसके अंतर्गत 11 महत्वपूर्ण यार्डों की पहचान की गई है, जिनमें से 4 यार्डों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है और शेष यार्डों का कार्य प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण किया जाएगा।

भोपाल रेलवे प्रशासन का सतत प्रयास है कि प्रत्येक यार्ड की संरचना यात्रियों की सुरक्षा, ट्रेनों की गति, समयबद्धता और परिचालन सुविधा के अनुसार उच्च मानकों पर आधारित हो। लूप लाइन और यार्ड अपग्रेडेशन के ये प्रयास रेल संरक्षा अभियान के अंतर्गत यात्रियों को एक संरक्षित, सहज और भरोसेमंद यात्रा अनुभव प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ में धूमधाम से निकाली शिव बारात

हिमालय की पुत्री माता सती का पार्वती के रूप में पुनर्जन्म हुआ था -कथा वाचक गुरु साहब शर्मा

सुबह सवेरे सोहागपुर। पिपरिया नर्मदापुरम राज्य मार्ग 22 पर स्थित शिव पार्वती मंदिर परिसर में श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ में कथा वाचक गुरु साहब शर्मा ने श्रद्धालु भक्तों को सुनाया।

भोलेनाथ अपने इष्ट का ध्यान कर रहे थे,तब माता सती ने पूछा आप किसका ध्यान कर रहे हैं।भोलेनाथ ने कहा मेरे प्रभु श्रीराम का , वनवास के रास्ते में चलते हुए जब माता सती ने रामजी को अपनी पत्नी के वियोग में लता, पता से सीता का पता पूछते देखा तो कहा क्या यह है आपके इष्ट ,जो पत्नी के वियोग में दर-दर भटक रहे हैं। भोलेशंकरजी ने माता सती को समझाने का प्रयास किया और कहा सती तुम परीक्षा ले लो। माता सती परीक्षा लेने के लिए पहुंची। विचार करने लगी की राम जी की परीक्षा किस रूप में कैसे ली जाए ।तब

माता सती ने सीता का रूप रखकर राम जी के सामने प्रकट हो गई। तभी प्रभु श्री राम ने माता सती को पहचान कर उन्हें प्रणाम किया। श्रीराम जी ने पूछा माता भोलेनाथ नहीं आए। परीक्षा लेने के बाद माता सती भोलेनाथ के पास पहुंची ।तभी भोलेनाथ ने पूरा दृश्य देख लिया कि क्या हुआ है। माता सती समझ गई की भोलेनाथ ने मेरा परित्याग कर दिया है इसके बाद दक्ष के यज्ञ विध्वंस में माता सती ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। बाद में हिमालय की पुत्री के रूप में माता सती का पार्वती के रूप में पुनर्जन्म हुआ। भगवान भोलेनाथ का माता पार्वती के साथ विवाह हुआ ।इससे पूर्व रामगंज औसे भगवान भोलेनाथ की बारात रामगंज तिराहे पलाश परिसर से होते हुए शिव पार्वती मंदिर परिसर की यज्ञशाला पहुंची।जहां बारातियों का घरातियों ने स्वागत किया। धूमधाम से भगवान भोलेनाथ का विवाह महोत्सव मनाया गया। आयोजन समिति के सदस्य शिव कुमार पटेल,धन सिंह रघुवंशी ने बताया कि 6 तारीख को राम कथा में राम जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इसके पूर्व कथावाचक रामकिशोर दुबे ने श्रोताओं को बताया कि जब-जब धर्म की हानि होती है असुरों का अत्याचार बढ़ता है पाप अनाचार बढ़ता है तब तब प्रभु इस धरा पर अवतार लेकर प्रकट होते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं पापियों का नाश करते हैं राम कथा सबको तारने का काम करती है रामचरितमानस एवं गंगाजी दोनों ही पापियों के पापों को धोने का काम करती है ।गंगा जी में स्नान करते समय यदि आदमी अधिक गहराई में चला गया तो डूब जाता है परंतु रामचरितमानस में व्यक्ति जितना अधिक गहराई में जाता है ।उतना ही उसे आनंद आता है ।गंगा जी में पाप कटते हैं, परंतु स्नान करने के उपरांत हमसे कोई ना कोई हम पाप जाने अनजाने में हो जाता है। परंतु रामचरितमानस में डूबने के बाद यह जो पाप करने की प्रवृत्ति है वह मूल रूप से नष्ट हो जाती है।

18 मई को अयोध्या बायपास पर जुटेंगे लोग; एनएचएआई चौड़ी करेगा सड़क

भोपाल (नप्र)। भोपाल के आसाराम तिराहे से रत्नागिरि तिराहा तक अयोध्या बायपास के चौड़ीकरण में 8000 पेड़ों को काटा जाएगा। इस प्रोजेक्ट को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) कर रही है। उन्होंने पेड़ काटने की अनुमति के लिए नगर निगम में आवेदन भी किया है। इसी बीच विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। 18 मई को इसे लेकर बड़ा आंदोलन करने की भी तैयारी है।

प्रदर्शन को लेकर रणनीति भी बनाई जा रही है। बैठकों का दौर भी चल रहा है। पर्यावरणविद् उमाशंकर तिवारी ने बताया कि पिछले दिनों शिवाजी नगर में बैठक हुई थी। इसमें निर्णय लिया गया कि 18 मई की शाम को अयोध्या बायपास पर आंदोलन किया जाएगा, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल होंगे। विकास जरूरी है, पर हरियाली के नाम पर ऐसा नहीं

भोपाल में 8 हजार पेड़ बचाने के लिए आंदोलन

होने देंगे। एनएचएआई को प्रोजेक्ट में बदलाव करना चाहिए। ताकि, प्रोजेक्ट भी पूरा हो और पेड़ भी न काटे जा सके।

इसलिए 10 लेन बनाया जा रहा अयोध्या बायपास- बता दें कि इस रोड पर 3 ब्लैक स्पॉट हैं, जहां साल भर में 30-35 लोगों की मौत हो जाती है। इसलिए सड़क को सर्विस लेन मिलाकर 10 लेन किया जा रहा है। विरोध की आशंका को देखते हुए एनएचएआई ने हाईकोर्ट और एनजीटी में कैविएट दायर की है। ताकि न्यायालय कोई भी स्टे देने से पहले एनएचएआई का पक्ष सुना जाए।अफसरों का कहना है कि अयोध्या बायपास के आसपास सिटी फॉरेस्ट डेवलप करने के लिए तैयार हैं।

पेड़ों को बांध चुके रक्षासूत्र- इससे पहले रविवार की शाम को भी लोगों ने प्रदर्शन किया था। बड़ी संख्या में लोगों रत्नागिरी तिराहे पर पहुंचकर पेड़ों को रक्षासूत्र बांधे थे। साथ ही उन्हें बचाने का संकल्प लिया था। आयोजन की अगुआई श्रमिक नेता दीपक गुप्ता ने की। उन्होंने कहा- यह सिर्फ पेड़ों की लड़ाई नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। हम इन पेड़ों को कटने नहीं देंगे। गुप्ता ने खुद पेड़ों को रक्षासूत्र बांधते हुए आंदोलन की शुरुआत की।

भोपाल समेत कई जिलों में तेज बारिश, ओले गिरे

24 घंटे में 50 शहरों-कस्बों में गिरा पानी, गुना में आंधी से शादी का टेंट उड़ा

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में सोमवार को एक बार फिर मौसम बदला है। भोपाल, ग्वालियर और शाजापुर समेत कई जिलों में बारिश हुई। तेज हवाओं के साथ ओले भी गिरे। बीते 24 घंटे में 50 शहरों-कस्बों में पानी गिरा। रायसेन में धूलभरी आंधी चली।

अगले कुछ घंटे के अंदर ग्वालियर-चंबल संभाग में ओले गिरने का अलर्ट है। इनमें मुरैना, गुना, विदिशा, ग्वालियर, शिवपुरी जिले के साथ पन्ना भी शामिल हैं। यहां गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। साथ ही 60 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से आंधी भी चल सकती है।

इसी तरह श्योपुर, भिंड, अशोकनगर, विदिशा, राजगढ़, आगर-मालवा, शाजापुर, खंडवा, छतरपुर, सतना, मैहर में हल्की बारिश हो सकती है। कटनी, सिवनी, मंडला, उमरिया, शहडोल, भोपाल, छिंदवाड़ा और रीवा जिलों में भी मौसम बदला रहेगा।

इस वजह से ऐसा मौसम

सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉ. अरुण शर्मा ने बताया कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ), साइक्लोनिक सर्कुलेशन और टर्फ की वजह से पूरे प्रदेश में मौसम बदला हुआ है। आज कुछ जिलों में ओले गिरने का अलर्ट है। कहीं-कहीं हवा की रफ्तार 50 से 60 किमी प्रतिघंटा तक रह सकती है।

इंदौर में 111 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से चली आंधी

इंदौर में रिकॉर्ड 111 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से आंधी चली। मौसम विभाग के अनुसार, सिंगरौली में 80 किमी, सीहोर में 78 किमी, हरदा में 74 किमी, आगर-मालवा में 69 किमी, भोपाल एयरपोर्ट के आसपास 65 किमी, उज्जैन में 58 किमी, बैतूल-शाजापुर में 49 किमी, पचमढ़ी-सिवनी में 41 किमी, छिंदवाड़ा में 39 किमी, नरसिंहपुर-सागर में 37 किमी, राजगढ़ में 36 किमी, अनूपपुर में 34 किमी, मंडला में 30 किमी और नीमच में 28 किमी प्रतिघंटा हवा की रफ्तार दर्ज की गई।

बाइक को टक्कर मारकर पलटी कार, 4 की मौत

मृतकों में तीन एक ही परिवार के, फलदान से लौट रहे थे

भिंड (नप्र)। भिंड में रविवार देर रात तेज रफ्तार कार और बाइक टकरा गए। टक्कर के बाद कार पलट गई। हादसे में बाइक सवार तीन और कार सवार एक शख्स की मौके पर ही जान चली गई। पांच गंभीर हैं। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक्सीडेंट नेशनल हाइवे 719 पर पिड़ौरा गांव के पास हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, कठमा गांव निवासी

बिहारीलाल बघेल (40), उनके चाचा सुजान सिंह बघेल (50) और सुजान का पुत्र ऋषिकेश बघेल (22) भिंड में फलदान कार्यक्रम में गए थे। रात करीब एक बजे घर लौट रहे थे। बाइक ऋषिकेश चला रहा था। इसी दौरान पोरसा से भिंड की ओर आ रही तेज रफ्तार कार नंबर 1902 ने एक वाहन को ओवरटेक करते हुए ऋषिकेश की बाइक को टक्कर मार दी।

कार सवार एक की मौत, पांच घायल

हादसे के बाद तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। कार सवार महमूद (23) पुत्र हमीद खान निवासी पोरसा की मौके पर ही मौत हो गई। सूरज (19), कल्लू (22), अंशु (22), शकील (24) और चालू (22) घायल हो गए। सभी को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल, भिंड पहुंचाया गया।विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह मौके से गुजर रहे थे। उन्होंने तुरंत गाड़ी रुकवाई। एम्बुलेंस और पुलिस को सूचना दी। घायलों को अस्पताल भिजवाने में मदद की। इसके बाद वे अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों को उचित उपचार के निर्देश दिए।

बांधवगढ़ में बजरंग बाघ का दीदार

ताला जोन में सड़क पार करता दिखा, पर्यटकों की जिप्सी रुकी

उमरिया (नप्र)। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को बाघ बजरंग का रोमांचक दर्शन हुआ। सोमवार को वायरल हुए वीडियो में बजरंग ने कुछ देर के लिए सफारी जिप्सियों को रोक दिया।

घटना ताला जोन के चक्रधरा क्षेत्र की है। पर्यटक जंगल में प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले

रहे थे। इसी दौरान बजरंग जंगल से वन मार्ग में आया। उसने सड़क पार की और फिर जंगल की ओर चला गया।

लगभग 7 वर्षीय बाघ बजरंग की टेरिटरी कोर एरिया के ताला, मगधी और खितौली जोन में है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 165 से अधिक बाघों का निवास है। इसके अलावा दो बाघिनों को बहेरहा इंक्लोजर में रखा गया है।

वक्फ बिल के विरोध में अभियान चलाएगी कांग्रेस

भोपाल (नप्र)। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में अब कांग्रेस भी जन जागरूकता अभियान चलाएगी। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की बैठक हुई। इस बैठक में मप्र कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की बैठक में पूर्व विधायक हमीद काजी और एआईसीसी अल्पसंख्यक विभाग के प्रभारी निजाम कुरैशी के साथ एमपी कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष शेख अलीम और सभी जिलों के अल्पसंख्यक कांग्रेस

के अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारी मौजूद थे।

कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष शेख अलीम ने मीडिया से कहा-वक्फ संशोधन बिल के विरोध में कानूनी लड़ाई कैसे लड़ना है। कैसे जन चेतना फैलाना है बैठक में इसकी पूरी कार्ययोजना बनाई है।

हमारे नेता राहुल गांधी के संविधान बचाओ अभियान, जातिगत जनगणना जैसे विषयों पर चर्चा हुई है। जिला अध्यक्षों ने जो बातें रखीं हैं उस पर हमने रणनीति बनाई है।

आतंकी हमले का मुसलमानों ने एकजुट विरोध किया- शेख अलीम ने कहा- अभी पहलगाम में जो घटना हुई। उस घटना पर बीजेपी को एक दिन भी हिन्दू-मुस्लिम करने का मौका नहीं मिला और हमारा अल्पसंख्यक समाज मैदान में आया। आतंकवाद और पहलगाम में हुए घिनौने कृत्य के विरोध में पूरे प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज ने पुतले जलाए। उसकी एक अलग ही पूरे प्रदेश में बात पहुंची कि हिन्दुस्तान का मुसलमान अपने देश और हिंदू भाईयों के साथ है। गंगा-जमुनी तहजीब के साथ है।

उज्जैन में दूर से दिखाई दी लपटें

महाकाल मंदिर परिसर में लगी आग

श्रद्धालुओं का प्रवेश रोकना पड़ा, कर्मचारी के दोनों हाथ झुलसे

उज्जैन (नप्र)। उज्जैन में महाकाल मंदिर परिसर में कंट्रोल रूम की छत पर आग लग गई। इससे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बैटरियां जल गईं। दूर से ही धुआं और आग की लपटें दिखाई दे रही थी। आग लगने के बाद मंदिर में भक्तों का प्रवेश रोकना पड़ा। आग बुझाने के दौरान एक कर्मचारी के दोनों हाथ झुलस गए।

घटना मंदिर के गेट नंबर 1 पर स्थित अवंतिका गेट के कंट्रोल रूम की छत पर हुई। सूचना मिलते ही दमकलें मौके पर पहुंची। कुछ ही देर बाद ही आग पर काबू पा लिया गया। इसके बाद मंदिर के गेट को दोबारा खोल दिया गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है।

कलेक्टर-एसपी भी मौके पर पहुंचे

आग लगने की सूचना मिलते ही कलेक्टर रोशन सिंह, महाकाल मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक, उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा, नगर निगम कमिश्नर आशीष पाठक सहित अधिकारी मौके पर पहुंचे।

आग में किसी जनहानि की सूचना नहीं

महाकाल मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया, कंट्रोल रूम की छत पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बैटरी में आग लगी थी, जिस पर तत्काल काबू पा लिया गया। इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है, केवल बैटरियों का ही नुकसान पहुंचा है।

मंदिर कर्मचारी के दोनों हाथ झुलसे

श्री महाकालेश्वर मंदिर के फैसिलिटी सेंटर व कंट्रोल रूम की छत पर सोमवार दोपहर में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एयर कंट्रोलिंग सिस्टम की बैटरी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। इस दौरान मंदिर समिति के प्रशासनिक भवन के बाहर मौजूद मंदिर समिति के कर्मचारी संतोष पाठक भी आग बुझाने छत पर पहुंचे थे। आग पर काबू पाने के लिए वहां जल रहे पाइप हटा रहे थे तभी उनके दोनों हाथ की हथेली आगे-पीछे से झुलस गई। मौके पर मौजूद अन्य लोगों ने पाठक को मंदिर के अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचाया। हालांकि पाठक पूरी तरह स्वस्थ है।

परीक्षा में पूछा-कहां है रानी दुर्गावती का मकबरा?

जबलपुर (नप्र)। जबलपुर का रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कभी रिजल्ट तो कभी एग्जाम सेंटर को लेकर सुर्खियों में रहता है। अब विश्वविद्यालय का एक और कारनामा सामने आया है। यहां तीन मई को बीएससी सेकेंड ईयर के फाउंडेशन कोर्स के एग्जाम में रानी दुर्गावती के समाधि स्थल को मकबरा बता दिया गया। प्रश्नपत्र में पूछा गया कि रानी दुर्गावती का मकबरा कहां पर है?

पेपर में इस तरह का सवाल पूछे जाने से लोगों में आक्रोश है। एनएसयूआई ने चेतावनी दी है कि अगर जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं हुई और उन्होंने माफी नहीं मांगी तो प्रदर्शन किया जाएगा। दूसरी ओर, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा- पता कर रहे हैं कि इस तरह की गलती कैसे हुई? यूनिवर्सिटी में 3 मई को बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर हुआ था, इसमें विवादित सवाल पूछा गया।

प्रश्न नंबर 42 में दिए थे चार ऑप्शन- बीएससी सेकेंड ईयर के फाउंडेशन कोर्स के पेपर में रानी दुर्गावती को लेकर प्रश्न नंबर 42 पूछा गया था। इसमें लिखा था- रानी दुर्गावती का मकबरा कहां बना है? जवाब में छात्रों को चार ऑप्शन दिए गए थे- (ए) बरेला (जबलपुर) (बी) बम्हानी (जबलपुर), (सी) चारगुंवा (जबलपुर) और (डी) डंडई (जबलपुर)। प्रश्न में समाधि स्थल की जगह मकबरा लिखा होने से छात्र कन्फ्यूज हो गए।

तेज हवाओं और बवंडर के कारण विंध्य क्षेत्र में चार ट्रांसमिशन टावर क्षतिग्रस्त

अमरकंटक में उत्पादित विद्युत की निकासी और पारेषण पर कोई प्रभाव नहीं : ऊर्जा मंत्री तोमर

भोपाल (नप्र)। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है गत दिवस तेज हवाओं और बवंडर के कारण विंध्य क्षेत्र स्थित मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी की 220 के.व्ही. अमरकंटक-सीधी तथा 220 के.व्ही. सीधी-रीवा ट्रांसमिशन सर्किट के चार टॉवर क्षतिग्रस्त हो गये। इस कारण अमरकंटक से सीधी 220 के.व्ही. सर्किट में विद्युत प्रवाह प्रभावित हुआ, लेकिन 220 के व्ही सबस्टेशन सीधी में वैकल्पिक ट्रांसमिशन सप्लाई उपलब्ध होने से क्षेत्र में इस कारण कोई विद्युत व्यवधान नहीं हुआ। साथ ही इससे अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन चचाई में उत्पादित विद्युत की निकासी एवं पारेषण पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा और अन्य सर्किट अनूपपुर एवं जबलपुर में विद्युत आपूर्ति निर्विघ्न बनी रही।

72 मीटर ऊँचा टावर भी हुआ क्षतिग्रस्त

एम पी ट्रांसको के मुख्य अभियंता श्री संदीप गायकवाड़ ने बताया कि विंध्य क्षेत्र में सोन नदी के आसपास मौसम के अचानक बिगड़ने से उपरोक्त दोनों सर्किट में दो टॉवर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए तथा दो अन्य टॉवर आंशिक रूप से प्रभावित हुए। इन टॉवरों में से एक 72 मीटर ऊँचाई का विशेष ट्रांसमिशन टॉवर है, जो सोन नदी क्रॉसिंग के लिए स्थापित किया गया था।

दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद, क्षतिग्रस्त टॉवरों की मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ कर दिया गया है। प्रभावित सर्किटों से विद्युत आपूर्ति पुनः बहाल करने में कम से कम तीन सप्ताह का समय लग सकता है।

नदी में मिले दो युवकों के शव, करंट से मौत

उमरिया में ईंट भट्टे जाते समय हादसा, ग्रामीणों ने शव रखकर किया रोड जाम, पुलिस ने समझाकर खुलवाया

उमरिया (नप्र)। उमरिया जिले के मानपुर थाना क्षेत्र के नरवार गांव में सोमवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई। भडारी नदी में बिजली के करंट की चपेट में आने से दो युवकों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान पुष्पेंद्र जायसवाल (35) और विपिन दाहिया के रूप में हुई है।

दोनों युवक रविवार की रात को गांव में मढ़वा कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसके बाद वे अपने ईंट भट्टे में काम करने के लिए नदी पार कर गये हुए थे। इसी दौरान वे नदी में बिजली के करंट की चपेट में आ गए। ग्रामीणों ने जब दोनों के शव नदी में देखे तो पुलिस को सूचना दी। मानपुर और ताला पुलिस मौके पर पहुंची। जांच में मौके से जीआई तार बरामद हुई है। चौकी प्रभारी वीरेंद्र यादव के अनुसार मामले की जांच की जा रही है।

जांच की मांग कर रहे ग्रामीण- नीतू जयसवाल के परिवार में पत्नी, एक बेटा और एक बेटी हैं। विपिन की शादी पिछले साल हुई थी। आज विपिन दाहिया के बहन की बारात आनी थी। घटना के बाद पूरे गांव के लोग मौके पर पहुंचे है। जांच की मांग को लेकर शव नहीं उठाने दे रहे हैं।सूचना मिलते ही मौके पर भीड़ लग गई, जांच की मांग को लेकर शव नहीं

उठाने दे रहे हैं। नीतू (पुष्पेंद्र) जयसवाल के जीजा चंद्र भान ने बताया कि हम चाहते हैं कि दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए। ईंट भट्टा में काम करने के लिए गये हुए थे। लौटते समय हादसा हुआ है। जांच होनी चाहिए।

युवकों की मौत के बाद ग्रामीणों ने ताला मार्ग पर सड़क जाम कर दिया। अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सहित राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, उन्होंने लगभग एक घंटे की समझाइश के बाद जाम खुलवाया। ग्रामीण शव का पीएम करवाने के लिए तैयार हो गए है।

अनुविभागीय अधिकारी नागेन्द्र सिंह ने बताया कि मौत को लेकर एसआईटी बना दी गई है। जांच की जा रही है। मैं स्वयं मौके पर जा रहा हूं।

निदेशक की गई कुर्सी !

मध्य प्रदेश नाटक विद्यालय का निदेशक अब कोई नया चेहरा ही होगा। निवृत्तमान निदेशक टीकम जोशी के कार्यकाल में वृद्धि की संभावना खत्म हो गई। गत 17 अप्रैल को कार्यकाल समाप्ति के बाद भी कुर्सी पर डटे जोशी बैक टू पवेलियन हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने विद्यालय के पूर्व निदेशक टीकम जोशी के सेवाकाल में वृद्धि के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। अब जल्दी ही नाट्य विद्यालय के निदेशक की नियुक्ति की जायेगी। संस्कृति संचालनालय ने इसके लिए राष्ट्रीय विज्ञापन भी जारी कर दिया है और निदेशक की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। बता दें कि निवृत्तमान निदेशक संघ पृष्ठभूमि के थे और वह कार्यकाल में वृद्धि के लिए संघ स्तर से सरकार पर दबाव भी बना रहे थे लेकिन उनके प्रयास काम नहीं आये। नाट्य विद्यालय के लिए कुछ खास ना कर पाने का खामियाजा पूर्व निदेशक के कार्यकाल वृद्धि में आड़े आया है।

मोहन का मंत्रालय

आशीष चौधरी

नेताजी परेशान, गायब समर्थक

लव जिहाद मामले में अपने खास समर्थकों का नाम सामने आने के बाद राजधानी के एक प्रभावी नेताजी परेशान है। नेता जी ने समर्थकों से दूरी बना ली या कहें कल तक खास क्षेत्रों में कदम से कदम मिलाकर चलने वाले यह समर्थक नेता जी के साथ अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि कालेज छात्राओं के अश्लील वीडियो और लव जिहाद मामले को लेकर एसआईटी की कार्रवाई के बाद राजधानी के नेता जी के हमेशा इर्द-गिर्द रहने वाले दोनो खास समर्थक दूर चले गए हैं। समर्थक उस क्लब के कर्ताधर्ता है जहां पर छात्राओं को लव जिहाद का सामना करना पड़ा। समर्थकों ने यह क्लब आरोपियों को बिना लिखा पढ़ी के दिलाने में मदद की थी। इसी बात को लेकर कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री ने बयान भी दिया था कि नेताजी आप चुप क्यों हैं ? पूर्व मंत्री के बयान के बाद नेताजी ने औपचारिक चुप्पी तोड़कर मामले में एक बयान दे इतिश्री कर ली। बता दें कि नेता जी का एक समर्थक जिला भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का सगा रिश्तेदार है।

मंत्री के करीबी को नहीं मिला रेस्टोरेंट

कई महीनो से विवादों से घिरे चले आ रहे राज्य सरकार के मंत्री के एक करीबी की भोपाल की प्राइम लोकेशन में रेस्टोरेंट चलाने की तमन्ना अधूरी रह गई है। मंत्री का करीबी रेस्टोरेंट चलाने के लिए अपनी राजनीतिक पहुंच का इस्तेमाल करता रहा लेकिन रेस्टोरेंट के संचालक से कब्जा खाली नहीं कर पाया और अब यह मामला कोर्ट चला गया है। सूत्र बताते हैं कि मंत्री के करीबी ने रेस्टोरेंट को खाली करने के लिए विभागीय अधिकारियों से लेकर पुलिस तक का दबाव बनाया लेकिन संचालक इसके दबाव में नहीं आए। विभाग के अधिकारियों ने रेस्टोरेंट तोड़ने की धमकी भी दी लेकिन संचालक टस से मस नहीं हुआ। विवश जोकर विभाग ने रेस्टोरेंट खाली करने के लिए नोटिस जारी किया। संचालक नोटिस लेकर कोर्ट

विवादों से नाता

राज्य सरकार के एक राज्यमंत्री का विवादों से नाता खत्म नहीं हो रहा है। ताजा विवाद एक संभाग में सामने आया जब दौरे पर मंत्री निकले और उन्हें वहां प्रोटोकॉल के अनुसार सम्मान नहीं मिला, तो उन्होंने अपने विभागीय अधिकारियों से न केवल कार्यवाही करवाई बल्कि सजा और जुर्माना दोनों करने की धमकी भी थी। पहली बार के यह विधायक लगातार विवादों में चले आ रहे हैं। इससे पहले विवाद अपने एक रिश्तेदार को लेकर पुलिस से हुआ था और वह खुद थाने में जाकर बैठ गए थे जबकि एक अन्य विवाद में वह टोल नाके पर खड़े होकर रात भर खनिज ट्रैकों की जप्ती करते रहे लेकिन सुबह होते ही विभाग के अधिकारियों ने ट्रैकों की परमिशन नियम अनुसार जांच कर छोड़ दिया।